शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in

हिंदी दैनिक

गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 12 | अंक : 291 | गुवाहाटी | गुरुवार, 28 मई, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक 10 जून को — पेज 2
महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के वॉकआउट पर भाजपा का हमला — पेज 3
पीएम मोदी ने राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का माध्यम ... — पेज 5
नार्वे शतरंज 2026 : प्रज्ञानंद को फिरोजा ने हराया, दिव्या देशमुख ने हम्पी को दी मात — पेज 7

असम विस में यूसीसी विधेयक पारित

गुवाहाटी (हि.स.)। असम विधानसभा में बुधवार को लंबी और तीखी बहस के बाद समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित कर दिया गया। इसके साथ ही असम यूसीसी पास करने वाला देश का तीसरा तथा पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन जाएगा। जिस समय यह विधेयक पास हुआ, उस समय सदन के अंदर दर्शक दीर्घा में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष तथा सांसद दिलीप सैकिया, केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री पवित्र मार्घेरिटा समेत कई भाजपा के नेता सदन में मौजूद थे। बिल के पास होते ही पूरा विधानसभा भवन जय श्रीराम एवं भारत माता के उद्घोष से गूंज उठा। विधानसभा में मौजूद सभी लोग उत्साहित हो गए थे। विधानसभा में विधेयक को सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन मिला, जबकि विपक्षी दलों ने इसके कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि यह कानून सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। विधानसभा में बहस के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह कानून व्यक्तिगत धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन विरोध के बावजूद विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। *समान नागरिक संहिता (यूसीसी), असम, 2026 बिल* पर पूरे दिन चली चर्चा के बाद, स्पीकर रंजीत कुमार दास ने मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से इसे पास कराने के लिए पेश करने को कहा। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें बिल को और ज्यादा चर्चा के लिए एक सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बात कही गई थी। इसके विरोध में विपक्षी सदस्य सदन के वेल (बीच के हिस्से) में आ गए और बिल पास होने तक लगातार नारेबाजी करते रहे। सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार *भारत माता की जय* और *जय श्री राम* के नारे लगाए जाने के बीच, स्पीकर ने बिल को ध्वनि मत से पास करने के लिए पेश किया। सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा बिल के पक्ष में वोट दिए जाने के बाद, स्पीकर ने घोषणा की कि मैं घोषणा करता हूं कि यह बिल पास हो गया है। जैसे ही यह बिल पास हुआ, सदन में जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत किया गया। बता दें कि, सोमवार को असम सरकार ने विधानसभा में *समान नागरिक संहिता (यूसीसी)* पर एक बिल पेश किया था। शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे कई निजी मामलों में धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए एक जैसे कानून तैयार करना था। इस बिल का मकसद बहुविवाह पर रोक लगाना और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य -शेष पृष्ठ दो पर

राष्ट्रपति की मंजूरी के तीन से छह महीने के भीतर ही लागू हो जाएगा कानून : सीएम

गुवाहाटी। असम विधानसभा ने बुधवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 पारित कर दिया। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने घोषणा की कि अब इस विधेयक को राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति के लिए भेजा जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद प्रेस से बात करते हुए शर्मा ने इसे एक *ऐतिहासिक* कदम बताया और सदन के सदस्यों को उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहा हूं और इस ऐतिहासिक विधेयक को अपनाने के लिए विधानसभा के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि विधेयक का पारित होना एक महत्वपूर्ण विधायी उपलब्धि है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन अभी भी कई महीनों दूर है। -शेष पृष्ठ दो पर

विपक्ष का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा-

यह सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है

गुवाहाटी। असम विधानसभा में बुधवार को विपक्षी सदस्यों ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर लाए गए विधेयक को *भाजपा का राजनीतिक एजेंडा* बताया और प्रस्तावित कानून को पारित करने से पहले सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श की मांग की। द *यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, 2026 विधेयक* पर चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों ने यह भी कहा कि यह समाज के एक विशेष वर्ग के अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस विधायक दल के नेता वाजेद अली चौधरी ने कहा कि समान नागरिक संहिता में जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, वे पहले से ही अलग-अलग कानूनों के माध्यम से लागू हैं। बाल विवाह, बहुविवाह, विवाह और तलाक का पंजीकरण, गुजारा भत्ता और अन्य मुद्दे विभिन्न कानूनों द्वारा शासित हैं। फिर यूसीसी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कानूनों का सरलीकरण नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को और अधिक जटिल बनाना है। चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा इसे केवल राजनीति के लिए लायी है। लोगों के निजी मामलों में हस्तक्षेप करना लोकतांत्रिक नहीं है। और जो कानून आदिवासियों को बाहर रखता है, उसे समान कैसे कहा जा सकता है? उन्होंने आरोप लगाया कि यूसीसी लाना बेरोजगारी, बाढ़ और सरकारी स्कूलों की स्थिति जैसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और *लिव-इन रिलेशनशिप* जैसे व्यक्तिगत मामलों पर एक समान कानून लागू करने के उद्देश्य से, असम सरकार ने सोमवार को समान नागरिक संहिता से संबंधित एक विधेयक पेश किया, जिसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और लिव-इन संबंधों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, विधेयक में कहा गया है कि यह असम में रहने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय पर लागू नहीं होगा। इसमें कई दंडात्मक प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें बहुविवाह या दो विवाह के लिए सात साल की कैद और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण न कराने पर तीन महीने की जेल शामिल है। चौधरी का समर्थन करते हुए कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकदर ने कहा कि 2018 में तत्कालीन विधि आयोग ने यूसीसी की आवश्यकता नहीं होने की -शेष पृष्ठ दो पर

असम में यूसीसी विधेयक पारित होने पर अमित शाह ने दी बधाई

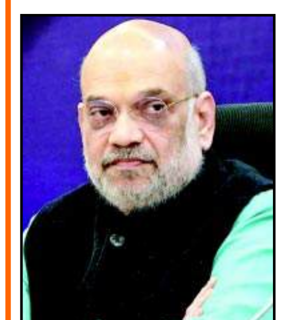

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित होने पर राज्य की जनता, मुख्यमंत्री और विधायकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से ही यूसीसी उसका संकल्प रहा है। अमित शाह ने बुधवार को एक्स पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासित राज्य सरकारें प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून स्थापित कर रही हैं। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम ने भी यूसीसी विधेयक पारित कर इतिहास रचा है। गृहमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और विधेयक का समर्थन करने वाले सभी विधायकों -शेष पृष्ठ दो पर

door graph Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

कांग्रेस में गीता और भागवत पर चर्चा करने का साहस नहीं है : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हि.स.)। असम विधानसभा में बुधवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज की कांग्रेस ने सांप्रदायिक शक्तियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब केवल कुरान और शरीयत की बात करती है तथा उसमें गीता और भागवत पर चर्चा करने का साहस नहीं बचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी जनजातीय और आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि *जहां बीमारी है, वहीं दवा दी गई है,* इसलिए स्वदेशी और जनजातीय समाज को इससे बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, संपत्ति और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में समान कानून लागू करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के शुरुआती दौर में कांग्रेस के नेताओं ने ही देश में यूसीसी का सपना देखा था। उन्होंने कहा कि आज की कांग्रेस, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांग्रेस नहीं रही। उन्होंने आरोप -शेष पृष्ठ दो पर

तीन जून के बाद हो सकता है असम मंत्रिमंडल का विस्तार : डॉ. शर्मा

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को संकेत दिया कि राज्य मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार अब 3 जून के बाद ही होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी और राज्यपाल की पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के कारण इसमें कुछ दिनों की देरी होगी। उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था कि यह जल्दी होगा, लेकिन 3 जून से पहले संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि राज्यपाल आधिकारिक दौरे पर मंगोलिया जा रहे हैं। शर्मा ने आगे कहा कि राज्यपाल की वापसी के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जो भी होगा, वह 3 जून के बाद ही होगा। धीरे-धीरे सब कुछ होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने संभावित फेरबदल या नए मंत्रियों को शामिल किए जाने को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन पिछले कई हफ्तों से असम में भाजपा नीत सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि प्रस्तावित विस्तार के जरिए मंत्रिपरिषद में खाली पदों को भरा जाएगा और कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के अलावा मंत्रिमंडल में केवल चार मंत्री शामिल हैं। राज्यपाल द्वारा जारी पूर्व अधिसूचना के अनुसार, भाजपा के वरिष्ठ नेता रामेश्वर तेली को ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, श्रम कल्याण तथा चाय जनजाति और आदिवासी कल्याण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चाय जनजाति और आदिवासी कल्याण विभाग को उनके कार्यभार में शामिल किए जाने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार असम के चाय बागान समुदायों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। वहीं, अतुल बोरा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, असम समझौता कार्यान्वयन, -शेष पृष्ठ दो पर

सुप्रभात

दुनिया की लगभग हर चीज सिर्फ ठोकर लगने से ही टूट जाती है, सिर्फ एक कामयाबी ही है, जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है।।

-अज्ञात

मणिपुर में पांच उग्रवादी कैडर गिरफ्तार हथियार व आईईडी बरामद, बंकर ध्वस्त

इंफाल (हि.स.)। मणिपुर पुलिस ने पिछले दो दिनों में पूरे मणिपुर में प्रतिबंधित उग्रवादी समूहों से जुड़े कई कथित भूमिगत सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही, पहाड़ी जिलों में अलग-अलग अभियानों के दौरान हथियार, विस्फोटक और संचार उपकरण भी बरामद किए गए हैं। मणिपुर पुलिस मुख्यालय के अनुसार प्रतिबंधित संगठन प्रीपाक के एक सक्रिय सदस्य, जिसकी पहचान इंफाल पूर्वी जिले के निंगोमथोंग सैरोम लीराक निवासी थिंगुजम गुलापी सिंह (45) के रूप में हुई है, को 26 मई को इंफाल पश्चिमी जिले के सिंगजामेई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत काकवा लिलांडो लंपक से गिरफ्तार किया गया। सुरक्षाकर्मियों ने उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन, एक आधार कार्ड और एक स्कूटर जब्त किया। इसके अलावा, सुरक्षा बलों ने पीएलए के एक कथित सक्रिय सदस्य, वाइखोम शांता सिंह उर्फ टोरबोट (32) को भी गिरफ्तार किया। वह सबुंगखोक मामंग लीकाई का निवासी है और उसे इंफाल पूर्वी जिले के लामलाई -शेष पृष्ठ दो पर

सीमा से 15 किमी. के दायरे में सभी अवैध ढांचे होंगे ध्वस्त : केंद्रीय गृहमंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को देश की सीमाओं के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माणों के खिलाफ *जीरो-टॉलरेंस* नीति को सख्ती से लागू करने और पिछले कुछ वर्षों में बने ऐसे सभी ढांचों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जिला मजिस्ट्रेटों को सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी बैंकों द्वारा बैंकिंग लेनदेन के कानूनी और वित्तीय अनुपालन को सुनिश्चित करने, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करने, उनके वित्तपोषण स्रोतों की जांच करने, फर्जी खातों और फर्जी कंपनियों का पता लगाने, फर्जी आधार कार्डों की पहचान करने और सीमा पार तस्करी को -शेष पृष्ठ दो पर

अमेरिका से डील फाइनल जल्द खुलेगा होर्मुज : ईरान

नई दिल्ली। ईरान-अमेरिका और इजरायल युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरानी सरकारी टीवी ने बताया कि अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का शुरूआती, अनौपचारिक मसौदा तैयार हो गया है। इस मसौदे के तहत ईरान एक महीने के अंदर हार्मुज जलडमरूमध्य से कमर्शियल शिपिंग को युद्ध से पहले स्तर पर बहाल करने को तैयार है। मसौदे के अनुसार अमेरिका-ईरान के आसपास अपनी सैन्य टुकड़ियों को वापस ले लेगा और नौसैनिक नाकाबंदी खत्म कर देगा। -शेष पृष्ठ दो पर

भारत में इबोला का कोई मामला नहीं : स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश में इबोला का एक भी मामला सामने नहीं आया है और सरकार इसे लेकर लगातार नजर रख रही है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला वायरस बीमारी के हालिया प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। एहतियात के तौर पर युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को शरीर में हल्के दर्द की शिकायत के बाद बेंगलुरु के राज्य संचालित एपिडेमिक डिजीज हॉस्पिटल में निगरानी और जांच के लिए आइसोलेशन में रखा गया था। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, व्यक्ति को शरीर दर्द के अलावा कोई अन्य गंभीर -शेष पृष्ठ दो पर

भीषण गर्मी के बीच प्रधानमंत्री ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की

नई दिल्ली (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति के बीच नागरिकों से सतर्क रहने और सभी आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहर निकलते समय पानी साथ रखने और जरूरतमंदों को पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर कई पोस्ट साझा करते हुए कहा कि अत्यधिक गर्मी सभी के लिए चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने लोगों को हीट एग्जॉशन के लक्षणों जैसे चक्कर आना, मतली और अत्यधिक थकान को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को कमजोरी, सिरदर्द या अस्वस्थता महसूस हो तो उसे तुरंत ठंडी और छायादार जगह पर ले जाकर पानी और ओआरएस उपलब्ध कराना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे, बुजुर्ग और बाहर काम करने वाले लोग अत्यधिक गर्मी में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि लक्षणों की अनदेखी करने पर स्थिति गंभीर होकर हीटस्ट्रोक का रूप ले सकती है। मोदी ने लोगों से अपने माता-पिता, दादा-दादी -शेष पृष्ठ दो पर

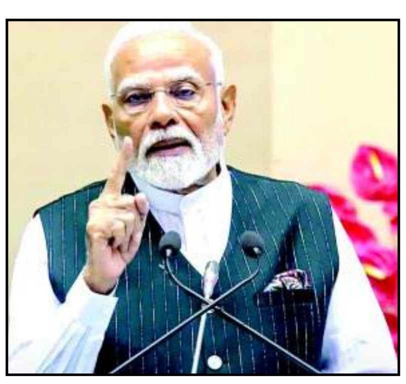

सिक्किम भी देश का पूर्ण साक्षर राज्य बना, राष्ट्रपति ने दी बधाई

गंगटोक (हि.स.)। सिक्किम भी देश का पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बुधवार को राजधानी गंगटोक में आयोजित सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में इस उपलब्धि की घोषणा की। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि थीं। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने उल्लास-नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने के लिए सिक्किम की जनता और सरकार को बधाई दी, जो 2027 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सिक्किम की सरकार और लोगों के सामूहिक प्रयासों को दर्शाती है। उन्होंने शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पर खुशी व्यक्त करते हुए साक्षरता को सशक्तिकरण और सामाजिक प्रगति का एक प्रमुख साधन बताया। मुख्यमंत्री तमांग ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सिक्किम यात्रा के दौरान उल्लास-नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक 10 जून को

मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों पर मंथन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक 10 जून को दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सहयोगी दलों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। सूत्रों के अनुसार, बैठक में मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। केंद्र के कल्याणकारी और विकास एजेंडे के लिए जनसंपर्क को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श होगा। चर्चा का केंद्र मोदी सरकार की प्रमुख कल्याणकारी पहलों को जमीनी स्तर तक ले जाना भी होगा। राज्यों में लाभार्थियों को केंद्र की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। इनमें कल्याण वितरण, बुनियादी ढांचा विकास और रोजगार सृजन शामिल हैं। परिषद की बैठक में केंद्र और एनडीए शासित राज्यों के बीच समन्वय की समीक्षा की जाएगी। विकास कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा। राज्यों के बीच शासन रणनीतियों को साझा करने पर भी ध्यान केंद्रित होगा। यह बैठक गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक अभ्यास मानी जा रही है। इसका उद्देश्य एनडीए सहयोगियों के बीच समन्वय को मजबूत करना है। शासन और कल्याण संबंधी मुद्दों के अलावा, बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक रोडमैप पर भी चर्चा हो सकती है। कई राज्यों में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार के विकास के एजेंडे को सुदृढ़ करने पर केंद्रित होगी। 10 जून की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भाजपा और उसके सहयोगी केंद्र की नीतिगत पहलों को उजागर कर रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर शासन के रिकॉर्ड पर भी प्रकाश डाला जा रहा है।

पूर्व सीएम के ठिकानों पर छापेमारी से भड़के सीपीएम कार्यकर्ता, ईडी की टीम पर किया हमला

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास समेत कई जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, राज्य में कुल 10 परिसरों पर तलाशी ली जा रही है। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत की है। जांच एजेंसी ने तिरुवनंतपुरम स्थित पिनराई विजयन के किराए के घर पर भी छापा मारा। मामले में आरोप है कोचिन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने 2018 से 2019 के बीच पिनराई विजयन की बेटी टी वीना की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपए का अवैध भुगतान किया था। आरोप है कि आईटी कंपनी ने सीएमआरएल को कोई सेवा नहीं दी थी। मंगलवार को केरल हाई कोर्ट ने सीएमआरएल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी ने ईडी की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। ईडी ने इन आरोपों की जांच के लिए साल 2024 में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन के आवास के बाहर बुधवार को हंगामा देखने को मिला। सीपीआई(एम) कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर हमला कर दिया। यह प्रदर्शन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केरल में 10 स्थानों पर की गई तलाशी के विरोध में किया गया। इन स्थानों में पिनराई विजयन का आवास भी शामिल है। ईडी यह कार्रवाई कोचिन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) मामले में कर रही है। प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। सीपीआई(एम) कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी राजनीतिक कारणों से कार्रवाई कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने तिरुवनंतपुरम में ईडी अधिकारियों के वाहन को निशाना बनाया। बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान ईडी की गाड़ी पर हमला किया गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी। ईडी ने बुधवार को केरल के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। यह कार्रवाई सीएमआरएल मामले में की जा रही जांच का हिस्सा है।

नगांव के ऐतिहासिक नामघर में चोरी से आक्रोश

नगांव (हिंस)। नगांव के आऊनीआटी बर नामघर (पूजा स्थल) में हुई चोरी की घटना से क्षेत्र में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है। इस घटना ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार, चोर नामघर से दानपात्र लूटकर ले गए। इतना ही नहीं, नामघर के पवित्र गुरु आसन को भी क्षतिग्रस्त कर अस्त-व्यस्त कर दिया गया। घटना के बाद आऊनीआटी के जागरूक लोगों के बीच भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू की गई है।

पुत्र के हमले में पिता की मौत

जोरहाट (हिंस)। जोरहाट जिले के मेलोपाम इलाके में पुत्र द्वारा किए गए हमले में पिता की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि जिले के मेलोपाम इलाके में धारदार हथियार से किए गए हमले में पिता की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सभाई दरबधारा के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने पिता की हत्या करने के आरोप में आरोपित पुत्र बिपलब दरबधारा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हत्या के पीछे पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह बताया है। पुलिस इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार आरोपित से सघन पूछताछ कर रही है।

तमिलनाडु के सीएम की प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री से शिष्टाचार भेंट

नई दिल्ली (हि.स.)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद इस महीने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद विजय की प्रधानमंत्री के साथ यह पहली औपचारिक मुलाकात थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच *एक्स* पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड यात्रा के दौरान अनाई मंगलम ताम्रपट्टिकाओं की बरामदगी और उन्हें भारत वापस लाने के प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री जोसेफ ने इस दौरान अपने राज्य से संबंधित विषयों का एक प्रतिवेदन भी प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने इसके बाद कर्तव्य भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। दिल्ली प्रवास के दौरान उनके कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात तय है। प्रधानमंत्री को सौंपे अपने प्रतिवेदन में उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में तमिलनाडु राज्य गीत *तमिल थाई वट्ठू* गाए जाने की परंपरा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा इस वर्ष जनवरी में जारी निर्देश के बाद कुछ सरकारी कार्यक्रमों में पहले राष्ट्र गान गाया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने गृह मंत्रालय से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया। बैठक में रक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर तथा सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स (सीएबीएस) स्थापित करने की मांग रखी।

अमेरिका की कागज मिल में केमिकल टैंक फटा, कई लोगों की मौत

वाशिंगटन (हि.स.)। अमेरिका की एक कागज (पेपर) और पल्प मिल में केमिकल टैंक फटने से कई लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मिल परिसर में लगभग 10 लोग गंभीर स्थित में मिले हैं। यह लोग केमिकल की चपेट में आने से झुलस गए। मिल प्रबंधन ने कहा है कि कई कर्मचारी लापता हैं। सरकारी अधिकारियों और प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि की कि मंगलवार सुबह हुए इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। एबीसी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, यह मिल (निप्पॉन डायनाववे पैकेजिंग कंपनी) अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में नहीं, बल्कि देश के पश्चिमोत्तर प्रांत वाशिंगटन के लॉन्गव्यू में स्थित है। अधिकारियों ने साफ किया है कि इस घटना से आसपास के नागरिकों को तत्काल कोई खतरा नहीं है। दमकल अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इस घटना की सूचना मंगलवार सुबह करीब 7:15 बजे मिली। बताया गया कि मिल में *व्हाइट लिकर* से भरा एक टैंक फट गया है। लॉन्गव्यू फायर बटालियन चीफ माइक गोरसच ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हालात स्थिर हैं। अभी बचाव कार्य चल रहा है। गोरसच के साथ मौजूद काउलिट्ज 2 फायर एंड रेस्क्यू के चीफ स्कॉट गोल्डस्टीन ने बताया कि मृतकों की संख्या का अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह बताने से मना कर दिया कि कितने लोग लापता हैं। गोरसच के मुताबिक, राहत और बचाव कार्य के दौरान फिसलने से एक दमकलकर्मी घायल हो गया। ओरेगन में पोर्टलैंड फायर एंड रेस्क्यू के प्रवक्ता रिक ग्रेव्स ने बताया कि जिन लोगों की हालत गंभीर है, उनका इलाज आसपास के चिकित्सा केंद्रों में किया जा रहा है। कुछ लोगों को बर्न सेंटर में भी दाखिल कराया गया है। निप्पॉन डायनाववे पैकेजिंग कंपनी की यह इकाई कोलंबिया नदी के किनारे स्थित है। यहां कंपनी की पल्प और पेपर मिल के साथ-साथ लिक्विड पैकेजिंग प्लांट भी है। यहां टिशू पेपर, प्रिंटिंग पेपर, कप, प्लेट, कार्टन और अन्य सामान बनाने के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है। प्रांत के पर्यावरण विभाग के अनुसार, इस मिल में लगभग 1,000 लोग काम करते हैं। गोल्डस्टीन ने बताया कि जो 80,000 गैलन (303,000 लीटर) क्षमता वाला टैंक फटा है, वह लगभग 60 फीसदा भरा था। यह केमिकल मुख्य रूप से सोडियम हाइड्रॉक्साइड और सोडियम सल्फाइड से मिलकर बनता है। इसका उपयोग लकड़ी को गलाकर क्राफ्ट पेपर बनाने में किया जाता है। गोल्डस्टीन ने कहा कि धमाके की वजह का पता लगाना अभी जल्दबाजी होगी।

असम विस के इतिहास में पहली बार मुस्लिम नेता को विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी

गुवाहाटी (हिंस)। असम विधानसभा के इतिहास में पहली बार किसी मुस्लिम विधायक को विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक वाजेद अली चौधुरी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। बुधवार को विपक्षी गठबंधन की ओर से इस नियुक्ति की घोषणा की गई। वाजेद अली चौधुरी अब विधानसभा में विपक्ष की ओर से नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही डॉ. जयप्रकाश दास को उप-विपक्ष नेता की जिम्मेदारी दी गई है। इन नियुक्तियों को आगामी विधानसभा सत्र से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है।

सड़क दुर्घटना में बाइक चालक की मौत

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी महानगर के दिसपुर पुलिस थाना के समीप हुए सड़क हादसे में बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि बीती रात असम सचिवालय के सामने तेज रफ्तार बाइक (एएस-01जे-3056) खंभे से जा टकराई जिसकी वजह से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दिसपुर पुलिस की टीम ने मृत बाइक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल भेज दिया है। अंतिम सूचना मिलने तक मृत युवक की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

पृष्ठ एक का शेष

असम विस में ...

करना है। हालांकि, इस बिल में यह भी कहा गया है कि यह कानून असम में रहने वाले किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। इस बिल में कई दंडात्मक उपायों का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें दो शादियां या बहुविवाह करने पर सात साल की जेल और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन न कराने पर तीन महीने की जेल की सजा शामिल है। इस बिल के तहत शादी के 60 दिनों के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा, जबकि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नियमों का पालन न करने पर सजा का भी प्रावधान है तय समय सीमा के भीतर जान-बूझकर शादी या तलाक का रजिस्ट्रेशन न करवाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

राष्ट्रपति की मंजूरी ...

शर्मा ने एक स्पष्ट प्रक्रियात्मक रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसका पालन इस कानून को लागू होने से पहले करना होगा। यह विधेयक सर्वप्रथम राज्यपाल के पास जाएगा, जिसके बाद इसे अंतिम स्वीकृति के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही यह प्रस्तावित कानून असम में लागू होगा। अब यह विधेयक महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलते ही, यह कानून असम में अक्षरशः लागू हो जाएगा, शर्मा ने कहा। मुख्यमंत्री ने आगे स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून के कार्यान्वयन से जुड़े कई नियमों को औपचारिक रूप से अधिसूचित करना होगा। उन्होंने कहा कि कानून के कार्यान्वयन से संबंधित छह से सात नियम हैं, जिनके लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी और अधिसूचना आवश्यक होगी। नियम पहले से ही तैयार हैं, लेकिन विधेयक को मंजूरी मिलने तक इन्हें अधिसूचित नहीं किया जा सकता है। शर्मा ने संकेत दिया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कार्यान्वयन की पूरी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया में तीन से छह महीने लग सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि पूरी प्रक्रिया में सामान्यतः तीन से छह महीने लग सकते हैं, जिसके बाद हम असम में समान नागरिक संहिता लागू कर सकेंगे। यूसीसी विधेयक का उद्देश्य धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाला एक समान नागरिक ढांचा स्थापित करना है। इसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार का कहना है कि यूसीसी का उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। हालांकि, विपक्षी दलों और कई संगठनों ने इस कानून के कुछ प्रावधानों और छूटों पर चिंता व्यक्त की है। विधानसभा द्वारा विधेयक पारित हो जाने के बाद, अब सारा ध्यान राजभवन और राष्ट्रपति भवन पर केंद्रित हो गया है और उस प्रशासनिक तंत्र पर जो यूसीसी को लोगों के लिए एक साकार रूप देने से पहले सक्रिय होना चाहिए।

यह सिर्फ राजनीतिक ...

राय दी थी। आयोग के अनुसार, यदि सरकार इसे लागू करना भी चाहती है तो उसे सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श करना चाहिए। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने विभिन्न धार्मिक संगठनों से चर्चा किए बिना यह विधेयक पेश कर दिया है। कई धर्म और सामाजिक समूह विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं रखते। हमारी पहचान *विविधता में एकता* है। सिकदर ने मांग की कि विधानसभा में इस विधेयक को पारित करने से पहले व्यापक परामर्श किया जाए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि मसौदा कानून को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में भारतीय जनता पार्टी की एक बूथ बैठक में कहा था कि एक घर के दो सदस्यों के लिए दो कानून नहीं हो सकते और एक घर के लिए एक ही कानून होना चाहिए। इसलिए यूसीसी का शीर्षक बदलना चाहिए क्योंकि यह राज्य के सभी लोगों को शामिल नहीं करता। सिकदर ने सवाल उठाया कि सरकार कुछ लोगों को इसमें शामिल न करके उनके साथ अन्याय क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक केवल भाजपा का राजनीतिक एजेंडा है, क्योंकि इन विषयों से जुड़े पहले से ही मौजूदा कानून मौजूद हैं। हमें यूसीसी की आवश्यकता नहीं है। एक अन्य कांग्रेस विधायक नुरुल होदा ने एक संशोधन प्रस्ताव लाते हुए राज्य के सभी जनजातियों और समुदायों को यूसीसी के दायरे में शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान कहता है कि जाति, पंथ और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। हम कुछ समूहों को किसी कानून के दायरे से बाहर नहीं रख सकते। एआईयूडीएफ विधायक मजीबुर रहमान ने कहा कि संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं, और असम सरकार ने यूसीसी को संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत लाया है, जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हालांकि, निदेशक सिद्धांतों के नाम पर मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता। एक प्रक्रिया चल रही है जिससे कुछ वर्गों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रहमान ने यह भी कहा कि मुख्य रूप से शरीयत पर आधारित मुस्लिम पर्सनल लॉ में वे सभी बिंदु पहले से ही मौजूद हैं जो प्रस्तावित यूसीसी में शामिल किए गए हैं।

असम में यूसीसी ...

को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर हिस्से में कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि असम विधानसभा में बुधवार को लंबी और तीखी बहस के बाद यूसीसी विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। इसके लागू होने के बाद असम यूसीसी लागू करने वाला देश का तीसरा और पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन जाएगा। विधेयक में बहुविवाह पर रोक, विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण तथा लिव-इन संबंधों के पंजीकरण जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। हालांकि, अनुसूचित जनजाति समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। विधानसभा में बहस के दौरान विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि यह कानून व्यक्तिगत धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करेगा, जबकि मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना है।

कांग्रेस में गीता और ...

लगाया कि कांग्रेस अब एक विशेष धार्मिक समूह का प्रतिनिधित्व कर रही है। सदन में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि असम यूसीसी लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बनेगा। उन्होंने दावा किया कि एनडीए की बड़ी चुनावी सफलता भी यूसीसी के पक्ष में जनता की इच्छा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद पुत्र और पुत्री को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा तथा वैवाहिक विवाद के दौरान पति को पत्नी का भरण-पोषण करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी के तहत दूसरी शादी करने पर सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान रहेगा। उन्होंने बहुविवाह के समर्थन को सभ्य समाज के लिए शर्मनाक बताया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से धर्मनिरपेक्षता और संविधान का प्रतिनिधित्व करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूसीसी का इतिहास बहुत पुराना है और भारत में वर्ष 1925 से ही इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

तीन जून के बाद हो ...

सीमा सुरक्षा एवं विकास तथा आबकारी विभाग सौंपे गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असम समझौते के प्रावधानों को लागू करने और राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से यह जिम्मेदारी काफी अहम है। इसके अलावा, बोड़ोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के नेता चरण बोड़ो को परिवहन विभाग और बोड़ोलैंड कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि इससे बोड़ोलैंड क्षेत्र में विकास कार्यों के समन्वय और परिवहन ढांचे को मजबूती मिलेगी। भाजपा की वरिष्ठ नेता अजंता नेउग को महिला एवं बाल विकास और पर्यटन विभाग का प्रभार सौंपा गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये विभाग राज्य सरकार की पर्यटन क्षमता बढ़ाने और महिलाओं व बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गौरतलब है कि इसी महीने हिमंत विश्व शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने नई मंत्रिपरिषद में शपथ ली थी।

मणिपुर में पांच उग्रवादी...

पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नोंगदा कामेंग क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियान में, आरपीएफ/पीएलए के कथित स्वयंभू कैप्टन अयेकपम धर्मेंद्र सिंह (48) को इरिलबुंग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत उसके मौजूदा आवास से पकड़ा गया। वह कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें धामेन, थावंतबा, कुंजो, ब्रोजेन और थावैलाकपा शामिल हैं। उसके पास से एक मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड बरामद किया गया। इससे पहले, मंगलवार को सुरक्षा बलों ने थौबल ज़िले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत फॉरेस्ट गेट के पास मयाई कीथेल से अलग-अलग भूमिगत संगठनों से जुड़े दो कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान चांगुबम नंगबा मेइतेई उर्फ मेइराबा उर्फ थौबा (21) के रूप में हुई, जो आरपीएफ/पीएलए से जुड़ा है, और एक किशोर के रूप में हुई, जो कथित तौर पर एनआरएफएम से जुड़ा है। इस बीच, सुरक्षा बलों ने उखरुल ज़िले के लिटान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक अभियान के दौरान तीन अवैध बंकरों को नष्ट कर दिया। एक बंकर पतलेइजांग गांव में स्थित था, जबकि अन्य दो बंकर टीएम कसम क्षेत्र के रौदेई गांव में नष्ट किए गए। सुरक्षाकर्मियों ने लगभग पांच किलो वजन का एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी), दो पॉम्पी बंदूकें, चार्जर के साथ दो बाओफेंग रेडियो सेट, 12 बोर के तीन जिंदा कारतूस और अलग-अलग कैलिबर के 12 खाली खोखे बरामद किए। चुराचांदपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हेंगकोट गांव के जंगल वाले इलाके में चलाए गए एक अलग तलाशी अभियान में, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। बरामद सामान में एक एमके-टू राइफल, दो मैगजीन वाली एक एके-47 राइफल, एक .303 राइफल, एक 12 बोर राइफल, कई देसी हथियार, दो एसबीएमएल बंदूकें, एक एसबीबीएल बंदूक और पांच आईईडी शामिल थे। अधिकारियों ने मौके से वायरलेस हैंडसेट, एक देसी लॉन्चर, मैगजीन पाउच, छलावरण वाले जंगल बूट, एक छलावरण वाली टोपी, जिंदा कारतूस और खाली कारतूस भी बरामद किए।

सीमा से 15 किमी. ...

नियंत्रित करने की बढ़ी हुई जिम्मेदारी सौंपी है। शाह ने बीकानेर में आयोजित एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से संबंधित सुरक्षा मुद्दों का आकलन किया। इससे पहले बीकानेर में सीमा चौकी पर बीएसएफ कर्मियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पिछली सरकारों ने सीमा सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका और उनके लिए आवश्यक सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने के मामले में महिला कर्मी पुरुषों से दो कदम आगे बढ़ चुकी हैं और 2030 तक सीमा क्षेत्रों में तैनात महिलाओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। शाह ने बताया कि राजस्थान में महिला कर्मियों के लिए 79 बैरक स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 67 का निर्माण लगभग 39 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। गृह मंत्री ने सोमवार को 14 बैरक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा संरक्षित सीमावर्ती क्षेत्रों में महिलाओं की तैनाती की स्थिति सुधारने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से 356 बैरक बनाए जाएंगे। शाह ने कहा कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक पार्श्व सड़क (लिटरल रोड) का निर्माण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि 1,096 किलोमीटर लंबी पार्श्व सड़क और 520 किलोमीटर लंबी अक्षीय सड़क (एक्ससीएल) बीएसएफ कर्मियों के लिए बेहतर सुविधाएं और संपर्क प्रदान करेगी। शाह ने कहा कि नयी डिजाइन की बाड़बंदी पर भी काम चल रहा है और राजस्थान में लगभग 180 सीमा चौकियों तक पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी गई है। शाह ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने वृक्षारोपण अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों ने लगभग 7.35 करोड़ पेड़ लगाए हैं। शाह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान को देखते हुए वृक्षारोपण लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने खेजड़ी का एक पौधा भी लगाया और इसे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण वृक्ष बताया।

अमेरिका से डील...

हालांकि यह प्रारंभिक समझौता सैन्य जहाजों को शामिल नहीं करता है। ईरान ओमान के सहयोग से होर्मुज में जहाजों की आवाजाही कंट्रोल करेगा। तेहरान ने साफ किया है कि बिना ठोस सत्यापन के कोई भी कदम नहीं उठाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अगर 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता हो जाता है तो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के रूप में अनुमोदित किया जा सकता है। यह एमओयू फरवरी में शुरू हुए ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद अप्रत्यक्ष वार्ताओं का नतीजा है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच केंद्रीय मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। युद्ध इस साल की शुरुआत में ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ने के बाद भड़का था। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, जिससे खाड़ी क्षेत्र में शिपिंग बुरी तरह प्रभावित हुई और अमेरिका भी संघर्ष में शामिल हो गया।

भीषण गर्मी के बीच...

और अन्य बुजुर्ग परिजनों का विशेष ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें नियमित रूप से फोन कर हालचाल लें और पर्याप्त पानी पीने, दोपहर की तेज धूप में बाहर न निकलने तथा पर्याप्त आराम करने की सलाह दें। प्रधानमंत्री ने भीषण गर्मी के दौरान पक्षियों और जानवरों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरों, बालकनी, छत, दुकानों और कार्यालयों के बाहर पानी से भरे छोटे बर्तन रखना प्यासे पक्षियों और जानवरों के लिए जीवनदायी साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें, अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। यदि संभव हो, तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। एक अन्य पोस्ट में लिखा कि जब भी संभव हो, अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी और अन्य प्रियजनों को फोन कर उनका हालचाल अवश्य पूछें। उन्हें पर्याप्त पानी पीने, दोपहर की तेज धूप में बाहर न निकलने और जितना हो सके, आराम करने की सलाह दें। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस प्रचंड गर्मी में हमें अपने आसपास के पशु-पक्षियों को भी नहीं भूलना चाहिए। अपने घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी से भरा एक छोटा-सा बर्तन रखना भी किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवनदान बन सकता है। आइए, इन कठिन दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक-दूसरे का ध्यान रखें।

सिक्किम भी देश...

सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने पर सिक्किम के लोगों को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि हमारे राज्य की शैक्षिक और सामाजिक प्रगति में एक निर्णायक मील का पत्थर है। यह हमारी इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि ज्ञान, गरिमा, सशक्तिकरण और समावेशी विकास की इस यात्रा में कोई भी वयस्क नागरिक पीछे न रह जाए। दूरदराज के गांवों से लेकर हर ब्लॉक और ग्राम पंचायत तक यह अभियान समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ सिक्किम के हर नुक्कड़ और कोने तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस चीज ने इस उपलब्धि को वास्तव में प्रेरणादायक बनाया, वह था शिक्षार्थियों का साहस, दृढ़ संकल्प और उत्साह, जिनमें से कई ने अपने जीवन में पहली बार पढ़ना और लिखना सीखा था। उनका दृढ़ संकल्प *साक्षर सिक्किम* की सच्ची भावना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग, सभी स्वयंसेवी शिक्षकों, अधिकारियों और इस अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हार्दिक आभार और सराहना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए सभी की निस्वार्थ सेवा, करुणा, धैर्य और अटूट प्रतिबद्धता ने इस परिवर्तनकारी पहल को एक बड़ी सफलता दिलाई है। उन्होंने कहा है कि साक्षरता केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता नहीं है, यह सशक्तिकरण, आत्मविश्वास, सामाजिक समानता और प्रगति की नींव है। उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाते हुए एक मजबूत, प्रबुद्ध, आत्मनिर्भर और समृद्ध सिक्किम के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कामना की कि यह उपलब्धि सभी को आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्कृष्टता, समावेशिता और मानव विकास की दिशा में प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित करें।

भारत में इबोला का ...

लक्षण नहीं थे। संदिग्ध मरीज का सैंपल जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में इबोला वायरस डिजीज की पुष्टि नहीं हुई और रिपोर्ट नेगेटिव आई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकार के साथ समन्वय में निगरानी बढ़ा दी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी जरूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मंत्रालय ने दोहराया कि भारत में इबोला वायरस बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया है। सरकार ने कहा कि देशभर में निर्धारित एंट्री प्वाइंट्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में स्क्रीनिंग और निगरानी जारी है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं, अफवाहों से बचें और केवल सरकारी व आधिकारिक स्त्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें।

महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के वॉकआउट पर भाजपा का हमला

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने असम विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) पर चर्चा के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए वॉकआउट की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि जब देश महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम का साक्षी बन रहा था, तब कांग्रेस ने चर्चा में रचनात्मक भागीदारी करने के बजाय विरोध प्रदर्शन और वॉकआउट का रास्ता चुना। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का यह रवैया उसके *महिला विरोधी मानसिकता* को उजागर करता है। भाजपा ने कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में महिला सशक्तिकरण के पक्ष में होती, तो वह विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार पर चर्चा से दूर नहीं रहती। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को केवल राजनीतिक नारे के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन महिलाओं की व्यापक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। भाजपा ने कांग्रेस शासित राज्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां महिलाओं की सुरक्षा, कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और संस्थागत सहयोग की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए भाजपा ने कहा कि केंद्र सरकार ने *महिला विकास* की सोच को *महिला नेतृत्व वाले विकास* में बदल दिया है। पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना और लखपति बाइदेउ जैसी योजनाओं को महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। भाजपा ने महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में परिसीमन प्रक्रिया का भी समर्थन किया और कहा कि परिसीमन कोई राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि संविधान के तहत आवश्यक प्रक्रिया है। पार्टी ने कहा कि देश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है, इसलिए निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उनकी उचित और समान भागीदारी सुनिश्चित करना लोकतंत्र की आवश्यकता है। असम प्रदेश भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सभी राजनीतिक दलों से इस ऐतिहासिक सुधार का समर्थन करने और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की।

विपक्ष के नेता की नियुक्ति से कांग्रेस की वास्तविक राजनीति उजागर : भूपेन बोरा

गुवाहाटी (हिंस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक भूपेन बोरा ने बुधवार को कहा कि विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी किसे दी गई है, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस वास्तव में किसका प्रतिनिधित्व करती है। बोरा बुधवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस फैसले के जरिए कांग्रेस की राजनीतिक सोच और उसका समर्थन आधार जनता के सामने आ गया है। भूपेन बोरा ने यह भी टिप्पणी की कि कांग्रेस के भीतर *एपीसीसी (आर)* की जो योजना थी, वह अब वास्तविकता में बदल गई है। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में विपक्षी दलों की नेतृत्व व्यवस्था और प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

यूसीसी पारित होने का असम भाजपा ने किया स्वागत

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने असम विधानसभा के 16वें सत्र के अंतिम दिन बुधवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी)-2026 विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया है। भाजपा मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन से जारी बयान में पार्टी प्रवक्ता डॉ. देवजीत महंत ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने इस ऐतिहासिक विधेयक को कानून का रूप देने में भूमिका निभाने वाले 102 एनडीए विधायकों को भी बधाई दी है। दिलीप सैकिया ने कहा कि असम की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में महिलाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से महिला सशक्तिकरण के अभियान को नई दिशा मिलेगी और राज्य के विकास को मजबूती प्राप्त होगी। कांग्रेस के विरोध पर निराशा जताते हुए सैकिया ने आरोप लगाया कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण से जुड़े *नारी शक्ति वंदन अधिनियम* का विरोध कर कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी महिला विरोधी मानसिकता को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि यह कानून समानता, सामाजिक न्याय और आधुनिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने आदिवासी और जनजातीय समुदायों की संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित किए हैं। सैकिया के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम ने संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और प्रगतिशील सुधारों की दिशा में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है।

कैग की रिपोर्ट में असम की मजबूत आर्थिक प्रगति का उल्लेख : डॉ. देवजीत महंत

गुवाहाटी (हिंस)। असम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. देवजीत महंत ने कहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की राज्य वित्त रिपोर्ट में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम की तेज आर्थिक प्रगति परिलक्षित हुई है। असम विधानसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार, राज्य का जीडीपी वर्ष 2015-16 के 2,27,958 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 6,43,667 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले चार वित्तीय वर्षों में राज्य ने औसतन 18 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। राष्ट्रीय जीडीपी में असम की हिस्सेदारी भी 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 1.95 प्रतिशत हो गई है। डॉ. महंत ने कहा कि सतत विकास, सुशासन और पारदर्शी प्रशासन के कारण असम देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग में 28वें स्थान से बढ़कर 17वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 1.5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि असम की बेरोजगारी दर घटकर 3.9 प्रतिशत हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 6.5 प्रतिशत से कम है। वहीं, राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 के 86,947 रुपए से बढ़कर 2024-25 में 1,59,185 रुपए हो गई है।

नगांव में भीषण सड़क हादसा, दो बाइक सवारों की मौत, दो महिलाएं घायल

नगांव (हिंस)। असम के नगांव जिले के रंगलू इलाके में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिला राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस से बुधवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईद की खरीदारी कर घर लौटने के दौरान बीती रात यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पर चल रही दो महिला राहगीरों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। दुर्घटना इतना जोरदार था कि बाइक सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान रकिबुल हुसैन और इक्रामुल हक के रूप में हुई है। घायल दोनों महिलाओं को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए नगांव सिविल अस्पताल भेजा गया है।

पिस्तौल दिखाकर छात्रा का अपहरण

गोलाघाट (हिंस)। राज्य में एक बार फिर अपहरण की घटना सामने आई है। गोलाघाट जिले के कमारबंधा क्षेत्र में विद्यालय जा रही एक छात्रा के अपहरण की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस द्वारा बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार, छात्रा रोज की तरह स्कूल के लिए निकली थी। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया और कथित तौर पर पिस्तौल दिखाकर उसे डराया-धमकाया। इसके बाद छात्रा को जबरन अपने साथ ले गए। घटना की सूचना पाकर छात्रा के परिवार वाले गांव के एक घर में छिपाकर रखी गई छात्रा तक पहुंचे। अपहर्ताओं के चंगुल से छूटने के बाद छात्रा ने मीडिया को बताया कि अज्ञात लोग उसे उस समय पिस्तौल दिखाकर घसीटकर अपने साथ ले गए जब वह साइकिल से स्कूल जा रही थी। उसे अपने ही गांव के एक घर में ले जाया गया जहां उसे धमकाया गया तथा बेच देने की बात कही गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों में भारी चिंता का माहौल है। लोगों की उग्र भीड़ पुलिस थाने तक पहुंची और थाने का घेराव कर लिया। लोग अपहर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है तथा मामले की जांच में जुट गई है।

धुबड़ी में राज्य स्तरीय जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

धुबड़ी (हिंस)। धुबड़ी सर्किट हाउस के सम्मेलन कक्ष में बुधवार को राज्य स्तरीय जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विकास आयुक्त अमर ज्योति बर्मन ने की। इसमें विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारी, सर्किल अधिकारी, बीडीओ तथा जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना 2027, सीएमएमएस पोर्टल, डिजिटल जनगणना, स्व-गणना प्रक्रिया और डेटा सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण उप महानिबंधक भारती चंद्रा और मास्टर ट्रेनर किशोर कुमार दास ने प्रदान किया। भारती चंद्रा ने कहा कि जनगणना देश की विकास योजनाओं की आधारशिला है और इसमें जुटाए गए आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रखे जाते हैं। उन्होंने बताया कि 2027 की जनगणना पहली बार स्मार्टफोन और डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी।

गवर्नर ने ईद-उल-जुहा की बधाई दी

गुवाहाटी। असम के गवर्नर श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने ईद-उल-जुहा के मौके पर असम के लोगों, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। अपने मैसेज में, गवर्नर ने कहा कि ईद-उल-जुहा त्याग, दया, विश्वास और भाईचारे के हमेशा रहने वाले मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस त्योहार को मेलजोल, शांति और आपसी सम्मान की भावना से मनाएं, साथ ही समाज के सभी वर्गों के बीच एकता के बंधन को मजबूत करें। श्री आचार्य ने उम्मीद जताई कि यह पवित्र मौका सभी को एक ज़्यादा दयालु और सबको साथ लेकर चलने वाला समाज बनाने के लिए सद्भावना, सहनशीलता और सामूहिक जिम्मेदारी के आदर्शों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। गवर्नर ने यह भी कहा कि असम की सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की समृद्ध परंपरा हमेशा से इसकी सबसे बड़ी ताकत रही है ।

जल्द सख्त होगा यातायात कानून : परिवहन मंत्री

गुवाहाटी (हिंस)। असम के परिवहन मंत्री चरण बोड़ो ने कहा कि राज्य में जल्द ही यातायात कानून को और सख्त बनाया जाएगा। मंत्री बुधवार को असम विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर आज विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। गुवाहाटी में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।

शोणितपुर संवाद के जरिए सेना-नागरिक समन्वय को मजबूत करने की पहल

तेजपुर (हिंस)। भारतीय सेना की गजराज कोर ने बुधवार को तेजपुर में *शोणितपुर संवाद* नामक सैन्य-नागरिक समन्वय संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य *समूहिक प्रयास से राष्ट्रनिर्माण* की भावना को मजबूत करना तथा *राष्ट्र सर्वोपरि* के सिद्धांत के तहत नागरिक और सैन्य संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। संवाद पहल के अंतर्गत समन्वय, आत्मनिर्भरता, मानसिक दृढ़ता, विश्वास और विकास को अमृतकाल के लक्ष्य के रूप में रेखांकित किया गया। संगोष्ठी में राज्य प्रशासन एवं विभिन्न प्रमुख संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में तेजपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, सशस्त्र सीमा बल के महानिरीक्षक, शोणितपुर रेंज के आईजी, वन विभाग के वरिष्ठ

अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, बार काउंसिल एवं नगरपालिका के प्रतिनिधि, तेजपुर के निजी अस्पतालों के प्रबंधन प्रतिनिधि, मंगलदै कौशल विकास केंद्र के प्राचार्य तथा तेजपुर एवं मिसामारी के अतिरिक्त उपायुक्त सहित कई महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए गजराज कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) ने *जेएआई* -जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन-को सुरक्षित, सशक्त और भविष्य के लिए तैयार भारत निर्माण का आधार बताया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संस्थागत समन्वय, संयुक्त प्रयास और समयबद्ध कार्यान्वयन पर जोर दिया। सैन्य-नागरिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै रिजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और गजराज कोर के अंतर्गत आने वाले सेना अस्पतालों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहयोग का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, प्रशिक्षण, शोध और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। यह पहल समेकित विकास, संस्थागत सहयोग और सामूहिक राष्ट्रनिर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

धुबड़ी: असम गण परिषद के अध्यक्ष ने ईद-उल-जुहा की शुभकामनाएं दी

धुबड़ी (विभास)। आज धुबड़ी जिला असम गण परिषद के जिला समिति के अध्यक्ष अब्दुल रशीद मिंधा ने ईद-उल-जुहा के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाईचारे, त्याग और संयम का संदेश दिया। उन्होंने धर्मावलंबियों को देश के प्रचलित कानून और अपने श्रद्धा के अनुसार शांतिपूर्ण कुर्बानी संपन्न करने के लिए आवाहन किया। साथ उन्होंने यह भी अनुरोध करते हुए कहा कि कुर्बानी के समय कोई धार्मिक या सामाजिक भाईचारा ना बिगड़े इसके लिए विशेष सावधान वरते और पवित्र ईद-उल-जुहा को शांति के साथ पालन करें। वहीं जिला प्रशासन भी ईद-उल-जुहा के अवसर सभी वर्गों से शांति बनाए रखने की अपली करते हुए कहा कि जिला में शासन व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके।

राज्यपाल कॉटन यूनिवर्सिटी के 126वें स्थापना दिवस में शामिल हुए

मेधावी स्टूडेंट्स को गवर्नर एक्सीलेंस अवॉर्ड दिए

गुवाहाटी। असम के गवर्नर श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आज कॉटन यूनिवर्सिटी के 126वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए और आज यहां यूनिवर्सिटी के केबीआर ऑडिटोरियम में मेधावी अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स को गवर्नर एक्सीलेंस अवॉर्ड दिए। सभा को संबोधित करते हुए, गवर्नर ने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और एल्युमनाई को बधाई दी और कॉटन यूनिवर्सिटी को नॉर्थईस्ट में हायर एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल जागृति और कल्चरल रेनेसां के सबसे प्रतिष्ठित सेंटर्स में से एक बताया। 1901 में अपनी स्थापना के बाद से इंस्टीट्यूशन की समृद्ध विरासत को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने असम के लिटरेरी, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। इंस्टीट्यूशन से जुड़े दिग्गजों को श्रद्धांजलि देते हुए, गवर्नर ने कहा कि डॉ. भूपेन हजारिका, डॉ. मामोनी रईसम गोस्वामी, भबेंद्र नाथ सैकिया, लक्ष्मी नंदन बोरा, हेम बरुआ जैसे कुछ नाम इस संस्थान की शानदार विरासत की हमेशा रहने वाली निशानी हैं। उन्होंने खुशी जताई कि स्टूडेंट्स की आज की पीढ़ी इन महान हस्तियों की बनाई बेहतरीन विरासत को आगे बढ़ा रही है। गवर्नर एक्सीलेंस अवॉर्ड पाने वालों को बधाई देते हुए,

श्री आचार्य ने कहा कि लोक भवन द्वारा 2022 में शुरू की गई इस पहल का मकसद स्टूडेंट्स के बीच पढ़ाई में काबिलियत, इनोवेशन और हेल्दी कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह स्कीम काबिल स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा का सोर्स बनकर उभरी है और यह समाज की उनकी लगन और कड़ी मेहनत को मिली पहचान को दिखाती है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के टॉपर्स स्टूडेंट्स को गवर्नर अवॉर्ड दिया गया, जिसमें एक गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट, किताबों का एक बंडल और हर एक को 5000 रुपए का चेक दिया गया। देश बनाने में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए, गवर्नर ने कहा कि किसी देश की असली ताकत उसकी युवा पीढ़ी में होती है, जिसका पक्का इरादा और विजन समाज को बदल सकता है और देश का भविष्य बना सकता है। उन्होंने स्टूडेंट्स से बड़े सपने देखने, चुनौतियों का सामना करने में निडर रहने और समाज और देश की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने की अपील की। भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर जोर देते हुए, श्री आचार्य ने कहा कि शिक्षक न केवल ज्ञान देते हैं बल्कि चरित्र भी बनाते हैं और जीवन में दिशा देते हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स को जिम्मेदार और जागरूक नागरिकों को तैयार करने में उनके योगदान के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद सहित भारतीय इतिहास की महान गुरु-शिष्य परंपराओं का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि हर महान हस्ती एक समर्पित गुरु के मार्गदर्शन में बनी है। राज्यपाल ने आगे कहा कि तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल कॉम्पिटिशन के दौर में, शिक्षा को एकेडमिक एक्सीलेंस से आगे बढ़कर स्किल्स, सेंसिटिविटी, इनोवेशन और नैतिक मूल्यों पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए। *विकसित भारत 2047* के विजन का जिक्र करते हुए, उन्होंने भरोसा जताया कि असम के युवा एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया उत्तरपूर्वी में *फिजिटल* शाखा तथा आरओएसएआरबी का शुभारंभ

गुवाहाटी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक- बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहक-केंद्रित नवाचार एवं समावेशी बैंकिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए, शिलांग, मेघालय में नई-पीढ़ी की फिजिटल शाखा तथा गुवाहाटी, असम में क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (आरओएसएआरबी) का शुभारंभ किया। मेघालय में हाल ही में शुरू की गई *फिजिटल ब्रांच* को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह ग्राहकों को डिजिटल सुविधा और व्यक्तिगत बैंकिंग सहायता दोनों का अनुभव प्रदान कर सके। उन्नत सेल्फ-सर्विस बैंकिंग सुविधाओं और समर्पित ग्राहक सहायता युक्त, इस शाखा का उद्देश्य एक आधुनिक, कुशल और ग्राहक-अनुकूल बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। गुवाहाटी में आरओएसएआरबी शाखा इस क्षेत्र में बैंक की दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली तथा समाधान के लिए फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगी जिससे विशेष निगरानी, बेहतर परिचालन क्षमता एवं उन्नत वसूली प्रणाली सुनिश्चित होगी। लाल सिंह, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा और शिब पद नायक, महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख, उत्तरपूर्वी राज्य अंचल की उपस्थिति में दोनों शाखाओं का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। डॉ. बीडीआर तिवारी (आईएएस), कमिश्नर व सचिव, मेघालय सरकार शिलांग में *फिजिटल शाखा* के उद्घाटन समारोह में के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर विश्वजीत स्वाईं (उप महाप्रबंधक, अनुपालन एवं आश्वासन, उत्तर-पूर्वी राज्य अंचल); कल्लोल विश्वास (उप महाप्रबंधक, अंचल निरीक्षण व लेखा परीक्षण विभाग, उत्तर-पूर्वी राज्य अंचल); पुनीत मिश्र (सहायक महाप्रबंधक एवं प्रभारी-राजभाषा एवं संसदीय समिति); दिवाकर झा (क्षेत्रीय प्रमुख-गुवाहाटी); प्रभात कुमार झा (सहायक महाप्रबंधक एवं उप क्षेत्रीय प्रमुख, गुवाहाटी क्षेत्र); प्रवीण कुमार सेठी (सहायक महाप्रबंधक एवं शाखा प्रमुख, एसएमई शाखा, गुवाहाटी क्षेत्र) तथा शाखा प्रमुख-त्रिलोचन साहू (मुख्य प्रबंधक, आरओएसएआरबी, गुवाहाटी क्षेत्र) सहित बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, सम्मानित ग्राहक तथा स्थानीय समुदाय के सदस्यों ने इन दोनों कार्यक्रमों में शिरकत की। इस अवसर पर लाल सिंह, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि शिलांग में फिजिटल शाखा और गुवाहाटी में आरओएसएआरबी का शुभारंभ बैंक ऑफ बड़ौदा के नवाचार, परिचालन उत्कृष्टता एवं ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग की दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। ये पहलें पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारी उपस्थिति को और सुदृढ़ करेंगी, साथ ही हमें बेहतर बैंकिंग एवं वसूली सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएंगी।

संपादकीय

कहीं मुनाफा, तो कोई 'बकरा'

पेट्रोल डीजल के खुदरा दाम 11 दिनों में चौथी बार बढ़ाए गए हैं। कुल वृद्धि करीब 7.50 रुपए प्रति लीटर हो गई है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह बढ़ोतरी 25 रुपए तक जा सकती है। फिर भी यह कोई नई, चौंका देने वाली खबर नहीं है, क्योंकि यूपीए सरकार में भी 150-166 फीसदी तक पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए थे और मौजूदा सरकार भी बढ़ा रही है। ये दाम ईरान युद्ध से उपजे संकट के कारण ही नहीं बढ़ाए गए, बल्कि सरकार की तेल कंपनियों की अपनी ही अर्थव्यवस्था है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और मंत्रालय की प्रवक्ता सुजाता शर्मा लगातार खुलासा करते रहे हैं कि तेल कंपनियां अब भी औसतन 600 करोड़ रुपए का घाटा झेल रही हैं। मंत्री जी ने तो यह घाटा 1 लाख करोड़ रुपए का बताया था और कई बार, कई मंचों पर ऐसे घाटे का रोना रोया था, लेकिन कुछ डाटा सामने आया है, जो मंत्रालय-मंत्री और तेल कंपनियों की 'झूठी अर्थव्यवस्था' को बेनकाब करता है। 2025-26 की आखिरी तिमाही (जनवरी-31 मार्च) के दौरान भारत सरकार की तीन विराट तेल कंपनियों ने 19,470 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। ईरान युद्ध 28 फरवरी को शुरू हो चुका था, लेकिन युद्ध के बावजूद अकेली 'इंडियन ऑयल' कंपनी ने 11,378 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। 'भारत पेट्रोलियम' और 'हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड' के मुनाफे अलग हैं। वित्त वर्ष की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2026 तक तीनों तेल कंपनियों ने कुल 77,280 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। मीडिया में कुछ आंकड़े भिन्न भी दिए गए हैं, जिनके अनुसार सरकारी तेल कंपनियों का मुनाफा 85,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। निष्कर्ष यह है कि तीनों तेल कंपनियों ने मोटा मुनाफा अर्जित किया है। आम भारतीय और उपभोक्ता सवाल कर सकते हैं कि 15-25 माह के दरमियान पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम क्यों बढ़ाए गए? तेल कंपनियां कुछ घाटा वहन नहीं कर सकतीं, तो क्या आम आदमी को ही बार-बार 'बलि का बकरा' बनाया जाता रहेगा? क्या तेल कंपनियों के मुनाफे आम करदाता, उपभोक्ता की जेब से ही वसूले नहीं जाते? तो फिर पेट्रोल-डीजल किस्तों में महंगे क्यों किए जा रहे हैं? सबसे संवेदनशील मुद्दा यह है कि मंत्री और मंत्रालय लगातार 'झूठ' क्यों परोसते रहे? यह संविधान और शपथ का भी उल्लंघन है। केंद्र सरकार पेट्रो उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क वसूलती है, तो राज्य सरकारें उस पर 2.29 लाख करोड़ रुपए 'वैट' के जरिए कमाती हैं। क्या लोकतंत्र में आम आदमी ही 'बकरा' बन कर रह गया है, जिसकी बार-बार बलि दी जाती है? 'वैट' कमाने में भी महाराष्ट्र, उप्र, गुजरात की सरकारें 'सर्वोच्च तीन' में शामिल हैं। तीनों राज्यों में ही भाजपा-एनडीए की सरकारें हैं। 'वैट' इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि केंद्र लंबे वक्त तक राज्य सरकारों को उनके हिस्से का पैसा नहीं देता, लिहाजा 'वैट' ही राज्य सरकारों का बुनियादी आर्थिक संसाधन है। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि हमारी राजनीति 'रेवड़ियों' और 'मुफ्तखोरी' की है, सबसिडी भी लाखों करोड़ों में देनी पड़ती है, आखिर पैसा कहां से आएगा? आम आदमी को ही चूसा जाएगा! दिलचस्प यह है कि अमरीका-ईरान के संभावित समझौते की उम्मीदों के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 104 डॉलर प्रति बैरल से 5 फीसदी घट कर 97-98 डॉलर पर आ गई हैं, लेकिन भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम चौथी बार बढ़ाए हैं! जब युद्ध के बावजूद तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही थीं, तो आम आदमी, आम उपभोक्ता को राहत क्यों नहीं दी गई? युद्ध शुरू होने के वक्त तो कच्चे तेल के दाम 70-72 डॉलर प्रति बैरल थे, लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल तब भी महंगे थे। इस महंगाई से आम आदमी की जेब पर 1500-2500 रुपए माहवार का बोझ बढ़ेगा। वह कहां से आमदनी लाएगा? वेतन, दिहाड़ी, मजदूरी, मेहनताना आदि तो यथावत हैं अथवा कम भी किए जाते रहे हैं। दरअसल तेल कंपनियों से केंद्र सरकार को 4.20 लाख करोड़ रुपए की सालाना कमाई होती है, लिहाजा साफ है कि मुनाफे में केंद्र सरकार भी 'परोक्ष हिस्सेदार' है! क्या मुनाफे और बकरे की इस अर्थव्यवस्था को देश का औसत नागरिक जानता है? चिंताजनक बात यह है कि दैनिक उपभोग की वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं। जहां खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं, वहीं फल और सब्जियां महंगी होने लगी हैं। महंगाई को रोक पाना केंद्र और राज्यों सरकारों के वश की बात नहीं रही है।

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और मंत्रालय की प्रवक्ता सुजाता शर्मा लगातार खुलासा करते रहे हैं कि तेल कंपनियां अब भी औसतन 600 करोड़ रुपए का घाटा झेल रही हैं। मंत्री जी ने तो यह घाटा 1 लाख करोड़ रुपए का बताया था और कई बार, कई मंचों पर ऐसे घाटे का रोना रोया था, लेकिन कुछ डाटा सामने आया है, जो मंत्रालय-मंत्री और तेल कंपनियों की 'झूठी अर्थव्यवस्था' को बेनकाब करता है। 2025-26 की आखिरी तिमाही (जनवरी-31 मार्च) के दौरान भारत सरकार की तीन विराट तेल कंपनियों ने 19,470 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। ईरान युद्ध 28 फरवरी को शुरू हो चुका था, लेकिन युद्ध के बावजूद अकेली 'इंडियन ऑयल' कंपनी ने 11,378 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। 'भारत पेट्रोलियम' और 'हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड' के मुनाफे अलग हैं। वित्त वर्ष की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2026 तक तीनों तेल कंपनियों ने कुल 77,280 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। मीडिया में कुछ आंकड़े भिन्न भी दिए गए हैं, जिनके अनुसार सरकारी तेल कंपनियों का मुनाफा 85,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है।

कुछ अलग

ग्राम स्वराज या स्वार्थ की राजनीति?

प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया मात्र नहीं हैं, अपितु प्रदेश के ग्रामीण लोकतंत्र की दिशा और दशा तय करने वाला महत्वपूर्ण अवसर भी हैं। प्रदेश की पंचायतें, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के हजारों पदों के लिए होने वाले ये चुनाव लोकतंत्र की उस आधारभूत इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां से जन भागीदारी, सामाजिक चेतना और ग्रामीण विकास की वास्तविक शुरुआत होती है। यह चुनाव प्रक्रिया केवलमात्र देश व प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार ही नहीं है, अपितु लोकतन्त्र की इस सूक्ष्म इकाई में जनप्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया में एक ऐसी प्रणाली है जो कि देश व प्रदेश के ग्रामीण लोकतन्त्र में सामाजिक चेतना और विकास की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। भारतवर्ष में आदिकाल से ही पंचायत व्यवस्था समाज में न्याय एवं सामाजिक चेतना की धुरी रही है, जो कि तत्कालीन समाज के विकास, न्याय एवं सामाजिक समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती रही है। देश व प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे आधारभूत इकाई है, जिसके माध्यम से प्रदेश के गांवों तक शासन, विकास और जनकल्याण की योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचती हैं। इस परिस्थिति में पंचायत प्रतिनिधियों के चयन के इस महापर्व में चयनित जन प्रतिनिधियों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और नैतिकता जैसे मूल तत्व अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश विगत कुछ दशकों से प्रदेश में पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार, पक्षपात, जातिवाद, भाई-भतीजावाद और पारदर्शिता के अभाव जैसी समस्याएं गंभीर रूप से प्रकट हो रही हैं।

मिट्टी के घड़े में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे पानी का थोड़ा-थोड़ा वाष्पीकरण होता रहता है

गर्मी में मटके का पानी क्यों है अमृत समान

डॉ. सत्यवान सौरभ

आधुनिक जीवनशैली में फ्रिज, एयरकंडीशनर और बोतलबंद पानी ने हमारे घरों में स्थायी जगह बना ली है, लेकिन इन सबके बीच मिट्टी के मटके का महत्व आज भी कम नहीं हुआ। गाँवों की चौपालों से लेकर शहरों की बालकनियों तक, मटके का पानी आज भी अपनी सौंधी खुशबू और प्राकृतिक ठंडक के कारण लोगों के दिलों में बसा हुआ है। यह केवल पानी रखने का साधन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, वैज्ञानिक समझ और प्रकृति से जुड़ी जीवनशैली का प्रतीक है। भारतीय समाज में मटके का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीना सीखा था। वे जानते थे कि हर समस्या का समाधान प्रकृति में ही छिपा है।

भीषण गर्मी के दिनों में जब सूर्य की तपिश धरती को झुलसाने लगती है, तब एक घूंट ठंडा पानी जीवन का सबसे बड़ा सुख प्रतीत होता है। आधुनिक जीवनशैली में फ्रिज, एयरकंडीशनर और बोतलबंद पानी ने हमारे घरों में स्थायी जगह बना ली है, लेकिन इन सबके बीच मिट्टी के मटके का महत्व आज भी कम नहीं हुआ। गाँवों की चौपालों से लेकर शहरों की बालकनियों तक, मटके का पानी आज भी अपनी सौंधी खुशबू और प्राकृतिक ठंडक के कारण लोगों के दिलों में बसा हुआ है। यह केवल पानी रखने का साधन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, वैज्ञानिक समझ और प्रकृति से जुड़ी जीवनशैली का प्रतीक है। भारतीय समाज में मटके का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीना सीखा था। वे जानते थे कि हर समस्या का समाधान प्रकृति में ही छिपा है। इसलिए गर्मी से राहत पाने के लिए उन्होंने मिट्टी के घड़ों का प्रयोग आरंभ किया। उस समय न बिजली थी, न फ्रिज और न आधुनिक तकनीक, फिर भी लोग स्वस्थ रहते थे क्योंकि उनकी जीवनशैली प्राकृतिक थी। मटके का पानी वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी माना गया है। मिट्टी के घड़े में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे पानी का थोड़ा-थोड़ा वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है और पानी स्वाभाविक रूप से ठंडा हो जाता है। यह ठंडक कृत्रिम नहीं होती, बल्कि शरीर के अनुकूल होती है। फ्रिज का अत्यधिक ठंडा पानी अचानक शरीर के तापमान को प्रभावित करता है, जिससे गला खराब होना, खांसी, जुकाम और पाचन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। इसके विपरीत मटके का पानी शरीर को धीरे-धीरे शीतलता प्रदान करता है। मिट्टी में प्राकृतिक क्षारीय तत्व पाए जाते हैं, जो पानी के साथ मिलकर शरीर के pH स्तर को संतुलित रखने में सहायता करते हैं। आज के समय में लोगों का खानपान अधिकतर अम्लीय हो गया है। फास्ट फूड, तले हुए पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स और अनियमित जीवनशैली के कारण एसिडिटी, गैस और अपच जैसी समस्याएँ सामान्य हो गई हैं। मटके का पानी इन समस्याओं को कम करने में सहायक होता है। यह पेट को ठंडक देता है और पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। डॉक्टरों का मानना है कि गर्मी के मौसम में शरीर से पसीने के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी और खनिज बाहर निकल जाते हैं। यदि समय पर इनकी पूर्ति न हो तो शरीर में कमजोरी, थकान और चक्कर आने जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। मटके का पानी शरीर को प्राकृतिक रूप से हाइड्रेट रखता है और आवश्यक खनिजों की पूर्ति में मदद करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम करने वाले किसान आज भी मटके का पानी पीना पसंद करते हैं। मटके के पानी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्राकृतिक शुद्धता है। आधुनिक समय में प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग तेजी से

बढ़ा है। गर्मी में जब ये बोतलें धूप के संपर्क में आती हैं, तो इनमें मौजूद हानिकारक रसायन पानी में मिल सकते हैं। वैज्ञानिक शोधों में यह बात सामने आई है कि प्लास्टिक में मौजूद BPA जैसे तत्व स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा, बोतलबंद पानी की गुणवत्ता भी हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। दूसरी ओर, मिट्टी का घड़ा पूरी तरह प्राकृतिक होता है और उसमें किसी प्रकार का रासायनिक खतरा नहीं होता। फ्रिज के पानी की तुलना में मटके का पानी अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। अत्यधिक ठंडा पानी कई बार शरीर के पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। भोजन के तुरंत बाद बहुत ठंडा पानी पीने से पाचन धीमा हो जाता है। वहीं मटके का पानी संतुलित तापमान पर रहता है, जिससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेद में भी अत्यधिक ठंडे पानी को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है, जबकि मिट्टी के घड़े के पानी को लाभकारी माना गया है। गर्मी में लू लगना भारत में एक गंभीर समस्या है। तापमान बढ़ने पर शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और व्यक्ति बेहोशी, उल्टी, सिरदर्द तथा कमजोरी का शिकार हो सकता है। मटके का पानी शरीर को अंदर से ठंडा रखता है और लू से बचाव में सहायक होता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा पसीने के माध्यम से अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालने में मदद करता है। यही कारण है कि पुराने समय में घरों, धर्मशालाओं और सार्वजनिक स्थानों पर यात्रियों के लिए मटकों में पानी रखा जाता था।भारत संबंधित उत्पाद मटके के पानी का एक महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा है। आज पूरी दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। हर वर्ष करोड़ों प्लास्टिक बोतलें कचरे के रूप में नदियों और समुद्रों में पहुँचती हैं। ये पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचाती हैं। इसके विपरीत मिट्टी का मटका पूरी तरह जैविक और पर्यावरण अनुकूल होता है। इसके निर्माण में किसी प्रकार के रसायन या मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। जब मटका पुराना हो जाता है, तब वह मिट्टी में मिलकर पुनः प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। मटके का उपयोग ग्रामीण कारीगरों और कुम्हारों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। आधुनिकता के दौर में प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों के बढ़ते उपयोग ने कुम्हारों के पारंपरिक व्यवसाय को प्रभावित किया है। यदि लोग फिर से मटकों का उपयोग बढ़ाएँ, तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एक साधारण मटका केवल पानी ठंडा नहीं करता, बल्कि एक कारीगर के घर का चूल्हा भी जलाता है। भारतीय संस्कृति में मिट्टी का विशेष महत्व रहा है। मिट्टी को माँ के समान माना गया है, क्योंकि वही हमें अन्न देती है और जीवन का आधार बनती है। मिट्टी के घड़े का पानी पीना केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। जब कोई व्यक्ति मटके का पानी पीता है, तो उसे एक अलग प्रकार की संतुष्टि और अपनापन महसूस होता है। मिट्टी की सौंधी सुगंध मन को शांति देती है और बचपन की यादों को ताजा कर देती है। आज के समय में लोग आधुनिकता की दौड़ में प्राकृतिक जीवनशैली से दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट और कृत्रिम सुविधाओं के बीच मनुष्य का संबंध प्रकृति से कमजोर पड़ता जा रहा है। ऐसे समय में मटके का पानी हमें यह याद दिलाता है कि सादगी में भी सुख छिपा होता है। प्रकृति के साथ जुड़कर ही मनुष्य स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकता है। हालाँकि, मटके का उपयोग करते समय कुछ सावधानियाँ भी आवश्यक हैं। मटके को नियमित रूप से साफ करना चाहिए ताकि उसमें गंदगी या बैक्टीरिया न पनपें। पानी को अधिक दिनों तक एक ही मटके में नहीं रखना चाहिए। यदि मटका पुराना या टूटा हुआ हो जाए, तो उसे बदल देना चाहिए। स्वच्छता बनाए रखने से ही मटके का पानी पूरी तरह लाभकारी बनता है। आजकल शहरों में भी मिट्टी के घड़ों की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग अपने घरों और कार्यालयों में मटका रखने लगे हैं। कई रेस्टोरेंट और होटल भी ग्राहकों को मटके का पानी परोस रहे हैं। यह परिवर्तन दर्शाता है कि लोग अब स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। सोशल मीडिया और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी प्राकृतिक जीवनशैली अपनाने पर जोर दे रहे हैं। शिक्षा संस्थानों और सामाजिक संगठनों को भी मटके के पानी के महत्व को बढ़ावा देना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को इसके वैज्ञानिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में बताया जाना चाहिए। यदि नई पीढ़ी प्रकृति के इन सरल उपायों को समझेगी, तभी स्वस्थ समाज का निर्माण संभव होगा। सरकार को भी प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पारंपरिक साधनों को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाने चाहिए। मीडिया की भूमिका भी इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। फिल्मों, विज्ञापनों और सामाजिक अभियानों के माध्यम से मटके के पानी के लाभों को प्रचारित किया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। हमें यह समझना होगा कि हर नई चीज बेहतर नहीं होती और हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती। मटके का पानी हमें आत्मनिर्भरता और सादगी का भी संदेश देता है। यह हमें बताता है कि प्रकृति ने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन दिए हैं।

देश दुनीया से

क्वाड विदेशी मंत्रियों की नई दिल्ली बैठक के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मायने

देखा जाए तो नई दिल्ली की यह बहुप्रतीक्षित क्वाड (Quad) बैठक यह बताती है कि आने वाले दशक में वैश्विक राजनीति का केंद्र यूरोप से हटकर इंडो-पैसिफिक बनने जा रहा है, और इस नई भू-राजनीतिक व्यवस्था में भारत केवल सहभागी नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसका सारा श्रेय मोदी प्रशासन और आरएसएस के प्रति समर्पित बुद्धिजीवियों को जाता है, जिन्होंने अपनी सधी हुई रणनीति का वैश्विक कमाल दिखा दिया। आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड क्या है? तो यह जान लीजिए कि Quadrilateral Security Dialogue यानी Quad चार लोकतांत्रिक देशों- भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया- का रणनीतिक समूह है, जिसका मुख्य उद्देश्य "फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक" को सुरक्षित रखना है। पहला, भारत की वैश्विक भूमिका मजबूतः दिल्ली में बैठक आयोजित होना यह दिखाता है कि India अब इंडो-पैसिफिक राजनीति का केंद्रीय खिलाड़ी बन चुका है। भारत, अमेरिका और पश्चिम के लिए संतुलित साझेदार है। वैश्विक दक्षिण (Global South) और पश्चिमी शक्तियों के बीच "सेतु" की भूमिका निभा रहा है। चीन के मुकाबले लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में उभर रहा है। दूसरा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लाभः Quad की समुद्री निगरानी पहल भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हिंद महासागर में भारतीय निगरानी क्षमता बढ़ेगी। चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी। भारतीय नौसेना को तकनीकी सहयोग मिलेगा। तीसरा, आर्थिक और तकनीकी अवसरः क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा सहयोग से भारत कोः नई निवेश संभावनाएँ, सप्लाई चेन हब बनने का मौका, मैन्युफैक्चरिंग विस्तार, और हाई-टेक उद्योगों में बढ़त मिल सकती है। चौथा, आतंकवाद पर भारत की चिंता को समर्थनः बैठक में आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद की निंदा की गई, जिसमें

पहलगाम हमले का भी उल्लेख हुआ। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक समर्थन है, विशेषकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर, और वैश्विक मंचों पर भारत की सुरक्षा चिंताओं को वैधता देने में। पांचवां, भारत-अमेरिका संबंधों में नई ऊर्जाः हाल के समय में टैरिफ और रणनीतिक मतभेदों के बावजूद बैठक ने दिखाया कि Quad ढांचा अभी भी मजबूत है। इससे संकेत मिलता है कि भारत और अमेरिका दोनों चीन को लेकर दीर्घकालिक सहयोग चाहते हैं। Quad व्यक्तिगत नेताओं से ऊपर उठकर संस्थागत रूप ले रहा है। पहला, चीन को सामरिक संदेशः बैठक का सबसे बड़ा संकेत चीन के लिए था। संयुक्त बयान में दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में "बलपूर्वक यथास्थिति बदलने" पर चिंता जताई गई। इसका अर्थ हुआ कि चीन की समुद्री सैन्य गतिविधियों पर निगरानी बढ़ेगी।इंडो-पैसिफिक में शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश तेज होगी। Quad अब केवल "संवाद मंच" नहीं बल्कि "रणनीतिक समन्वय मंच" बनता दिख रहा है। दूसरा, इंडो-पैसिफिक में नई भू-राजनीतिक धुरीः Quad देशों ने समुद्री निगरानी, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सुरक्षा पर नई पहलें शुरू कीं। फिजी में संयुक्त पोर्ट परियोजना इसकी मिसाल है। इससे प्रशांत द्वीपीय देशों में चीन का प्रभाव संतुलित करने की कोशिश होगी। हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक नई रणनीतिक कनेक्टिविटी बनेगी। छोटे देशों को "चीनी कर्ज कूटनीति" का विकल्प मिलेगा। तीसरा, सप्लाई चेन और क्रिटिकल मिनरल्स की राजनीति Quad ने क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा सुरक्षा पर नया फ्रेमवर्क बनाया। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकिः चीन रेयर अर्थ मिनरल्स में वैश्विक प्रभुत्व रखता है। सेमीकंडक्टर, रक्षा और AI उद्योग इन खनिजों पर निर्भर हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर चीन-निर्भरता कम करना चाहते हैं। चौथा, पश्चिम एशिया संकट और समुद्री व्यापारः बैठक में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी की सुरक्षा पर विशेष चर्चा हुई। इसके मायने ये हुए कि ईरान-इजरायल तनाव का असर वैश्विक व्यापार पर पड़ रहा है। क्वाड (Quad) वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। ऊर्जा आपूर्ति और तेल कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश है। पांचवां, "एशियाई नैटोर की बहस तेजः चीन लगातार क्वाड (Quad) को "ब्लॉक राजनीति" कहता रहा है। हालांकि क्वाड (Quad) खुद को नैटो (NATO) नहीं मानता, लेकिन सैन्य सहयोग बढ़ रहा है। समुद्री निगरानी और तकनीकी साझेदारी गहरी हो रही है। साझा सुरक्षा सोच विकसित हो रही है। सच कहूं तो नई दिल्ली की यह क्वाड (Quad) बैठक बताती है कि आने वाले दशक में वैश्विक राजनीति का केंद्र यूरोप से हटकर इंडो-पैसिफिक बनने जा रहा है। और इस नई भू-राजनीतिक व्यवस्था में भारत केवल सहभागी नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है।

आप का नजरीया

शहरी विकास की विडंबनाएं

पर्वतीय विडंबनाओं पर शहरी ताज को संवारने की घोषणा करते हुए, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बेंगलुरू मॉडल को अपनाने की इच्छा जाहिर की है। कोई भी मॉडल श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन इसकी शर्तें राजनीति से ऊपर और लाजिमी सुधारों के साथ ही पूरी हो सकती हैं। हिमाचल के शहरों में बेंगलुरू की आत्मा का आयात एक बड़ी घोषणा है, लेकिन इससे पहले कई सवालों के अर्थ खोजने होंगे। कुछ दशक पहले शिमला विकास प्राधिकरण का गठन हुआ, तो फिर इसे निरस्त क्यों किया गया। शिमला के साथ न्यू शिमला के विकास को अगर देखें, तो मालूम होगा कि हम कितने पानी में हैं। बेंगलुरू केवल शहर की कवायद नहीं, मैट्रो सिटी के नक्शे को आगे बढ़ाने का सिस्टम है। स्मार्ट सिटी तो शिमला और धर्मशाला भी बनने थे, तो इनकी असफलता या अपूर्णता के लिए सरकारें ही दोषी क्यों मानी गईं। दरअसल हिमाचल का शहरी विकास टीसीपी विभाग की क्षमता से ऊपर है, शहरों को स्मार्ट स्थिति तक ले जाना तथा कायम रखना। हमने अंग्रेजों के बसाये शहर बर्बाद किए तो इसलिए कि वहां से शहरी तहजीब को ही तिलांजलि दे दी गई। कभी शिमला अपने स्वच्छ पांवों, खुली हवा में ताकतवर फेफड़ों और पर्वतीय आचार संहिता से चलता था, लेकिन आज ग्रीन बेल्ट की तौहीन, जल निकासी के रास्तों और पहाड़ी परिवेश के उल्लंघन में चलता है। मंत्री जरा टीसीपी फाइल खोलकर यह बताएं कि पिछले तीन दशकों में शहरी कानूनों की कुर्बानियों पर शिमला कहां पहुंच गया। क्या हमने सोचा कि शिमला और आसपास फैलते शहरीकरण को 'राज्य राजधानी क्षेत्र' परियोजना के तहत विकसित करने की जरूरत है। क्या हमने प्रदेश की शहरी ग्रोथ का मूल्यांकन करते हुए शहरों का वर्गीकरण किया। मनाली का विकास कुल्लू की तरह नहीं हो सकता। इसी तरह मंडी और सुंदरनगर के विकास मॉडल में अंतर होगा। हिमाचल टेंपल सिटी आज भी विकास की खासियत चाहते हैं। पर्यटक शहर, शिक्षा के शहर, सांस्कृतिक-आर्थिक और प्रशासनिक शहरों की पहले खासियत तो तय कीजिए। आश्चर्य यह कि शहरी विकास मांग आधारित नहीं, बल्कि राजनीति से संचालित है। यही वजह है कि शहरों में न ढंग के बस स्टैंड, न पार्क, न पार्किंग स्थल और न ही खेल के मैदान विकसित हुए। शहर के जो मॉडल शिमला थे, वे भी हमने बर्बाद कर दिए। मसलन वाहन प्रतिबंधित बाजार और माल रोड अगर हर शहर में तय हो जाएं तो बदलाव आ जाएगा। इसी तरह शहरों के परिवहन को लेकर एलिवेटिड रोड, रज्जु मार्ग तथा झूला पुल परियोजनाएं अमल में आएं तो पैदल चलने के आसान रास्ते बनेंगे। बहरहाल हिमाचल में तीन नए शहरों की बात हो रही है, लेकिन ये भी पारंपरिक शहरों को शायद ही राहत दें। अगर ये आर्थिक, प्रोफेशनल, आईटी, मेडिकल सिटी या औद्योगिक साबित होते हैं, तो भी नक्शे पर गुरूर आएगा, लेकिन यहां तो बस्ती बसाने का लक्ष्य होना चाहिए। हिमाचल में दो या तीन शहरों को मिला कर कलस्टर योजनाएं बनाने की जरूरतें हैं ताकि शहरी और ग्रामीण जनता को आधारभूत सुविधाएं मिलें। इसके लिए पूरे प्रदेश में कम से कम छह शहरी विकास प्राधिकरणों का गठन करना ही पड़ेगा। बेशक बेंगलुरू मॉडल उत्साहित कर रहा हो, लेकिन हिमाचल की जनता जब तक तमाम सुविधाओं के एवज में कर अदायगी नहीं करेगी, हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

हिमाचल के शहरों में बेंगलुरू की आत्मा का आयात एक बड़ी घोषणा है, लेकिन इससे पहले कई सवालों के अर्थ खोजने होंगे। कुछ दशक पहले शिमला विकास प्राधिकरण का गठन हुआ, तो फिर इसे निरस्त क्यों किया गया। शिमला के साथ न्यू शिमला के विकास को अगर देखें, तो मालूम होगा कि हम कितने पानी में हैं। बेंगलुरू केवल शहर की कवायद नहीं, मैट्रो सिटी के नक्शे को आगे बढ़ाने का सिस्टम है। स्मार्ट सिटी तो शिमला और धर्मशाला भी बनने थे, तो इनकी असफलता या अपूर्णता के लिए सरकारें ही दोषी क्यों मानी गईं। दरअसल हिमाचल का शहरी विकास टीसीपी विभाग की क्षमता से ऊपर है, शहरों को स्मार्ट स्थिति तक ले जाना तथा कायम रखना। हमने अंग्रेजों के बसाये शहर बर्बाद किए तो इसलिए कि वहां से शहरी तहजीब को ही तिलांजलि दे दी गई। कभी शिमला अपने स्वच्छ पांवों, खुली हवा में ताकतवर फेफड़ों और पर्वतीय आचार संहिता से चलता था, लेकिन आज ग्रीन बेल्ट की तौहीन, जल निकासी के रास्तों और पहाड़ी परिवेश के उल्लंघन में चलता है। मंत्री जरा टीसीपी फाइल खोलकर यह बताएं कि पिछले तीन दशकों में शहरी कानूनों की कुर्बानियों पर शिमला कहां पहुंच गया। क्या हमने सोचा कि शिमला और आसपास फैलते शहरीकरण को 'राज्य राजधानी क्षेत्र' परियोजना के तहत विकसित करने की जरूरत है।

दृष्टि कोण

संकटग्रस्त विश्व में भारत की आर्थिक राह

हम सभी देख रहे हैं कि इक्कीसवीं सदी का विश्व वैज्ञानिक उन्नतियों के बाद भी अनेक प्राकृतिक-कृत्रिम बाधाओं से ग्रस्त है। कोरोना का कालखंड इसमें सबसे बड़ी बाधा रहा। इसके बाद अमरीका, रूस, ईरान, भारत, पाकिस्तान, यूक्रेन, इजरायल, खाड़ी के देशों सहित दुनिया के पंद्रह-बीस देश निरंतर युद्ध में उलझे हुए हैं, जिन पर निरंतर चर्चा हो रही है। नवीनतम अमरीका-इजरायल बनाम ईरान के युद्ध ने विश्व के सामने ऊर्जा की कठोर समस्याएं खड़ी कर दी हैं। अमरीका एवं इजरायल के द्वारा की गई बर्बादी का बदला ईरान तेल व गैस आपूर्ति के प्रमुख मार्ग होर्मुज को बंद कर, अवैध आवागमन शुल्क लेकर एवं बाधासंभावित बनाकर ले रहा है। ईरान के इस कर्म से दुनिया के विभिन्न देशों तक उनकी आवश्यकता का तेल तथा गैस सुगमता से नहीं पहुंच पा रही है। जो पहुंच भी रही है, वह भी अत्यंत महंगी होकर। उक्त देशों के चर्चित युद्ध के अतिरिक्त गुमनाम देशों के भी अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध चल रहे हैं। यदि पड़ोसी देशों के साथ उनका युद्ध नहीं भी चल रहा है, किंतु उनके अपने ही देश में अलग-अलग रक्तरंजित संघर्ष निरंतर हो रहे हैं। चूंकि ये देश बड़े एवं संपन्न देश नहीं हैं, इसीलिए इनके युद्धक तथा स्वदेशी संघर्षों के समाचार अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुख्य जनसंचार माध्यमों पर नहीं होते। युद्धकेंद्रित इन समस्याओं के साथ-साथ प्राकृतिक अस्थिरता एवं प्रतिकूलता की स्थितियां भी नित नए-नए विकृत ढंग से उत्पन्न हो रही हैं। यदि भारत के संदर्भ में युद्धक तथा प्रकृति आधारित समस्याओं का विश्लेषण किया जाए तो इनका अंत होता हुआ नहीं दिखाई देता। वैसे तो गृहमंत्री ने जनसंचार माध्यम पर गर्वोक्ति के साथ घोषित कर दिया है कि भारत अब नक्सल-समस्या से मुक्त हो चुका है। यह अच्छी बात है। यदि मंत्री जी की घोषणा पूर्णतः सत्य है तो यह इस शासन की विशेष उपलब्धि है, किंतु इस उपलब्धि के साथ बाद में कोई किंतु-परंतु नहीं होना चाहिए। भविष्य में कहीं ऐसा कुछ सुनने या पढ़ने को न मिल जाए कि नक्सलियों का उन्मूलन बड़े पूंजीपतियों के दबाव में उन

वनों के भौतिक-औद्योगिक उपयोग के लिए किया गया है, जहां ऐसे पूंजीपति अपनी नवीन महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आरंभ करना चाहते हैं। नक्सल-समस्या से तो देश मुक्त हो चुका है, किंतु वैश्विक ऊर्जा व आपूर्ति संकट से घिर चुका है। इसके अतिरिक्त देश में बहुत-सी ऐसी समस्याएं हैं, जो केवल और केवल सामान्य मानव के स्तर पर जीवन जीकर ही अनुभव की जा सकती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप में विपक्ष में थी और उसकी बड़ी शासकीय स्थापना नहीं थी, तो प्रायः वह कांग्रेस तथा अन्य सत्तारूढ़ दलों पर अनेक आरोप लगाया करती थी। देश की समस्याओं का समाधान नहीं करने के लिए ऐसे दलों को भारत के लौकिक न्यायालय में खड़ा कर प्रश्न पूछा करती थी। भाजपा का तत्कालीन सत्ताधारी दलों से प्रश्न करना कभी नहीं रुका। सत्ताधारी दलों की मनमानी और समस्याओं का समाधान न करने की प्रवृत्ति भी ज्यों की त्यों बनी रही। किंतु वर्तमान समय तो शासन में स्थापना के दृष्टिकोण से भाजपा के अनुकूल है। इस समय वह 20 प्रदेशों तथा 2 केंद्रशासित प्रदेशों में सत्तारूढ़ है। वह केवल 8 प्रदेशों व 6 केंद्रशासित प्रदेशों में सत्ता में नहीं है। इसके बाद भी अनेक सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं बनी हुई हैं और हर नए दिवस में पहले से अधिक विकराल हो रही हैं। जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर तथा दक्षिण भारतीय राज्यों की सीमाओं के समीप स्थित पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका तथा म्यांमार के माध्यम से भारत में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की जाती रही हैं।

गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर विहिप का प्रदर्शन

प्रयागराज (हिंस)। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) गोरक्षा विभाग के प्रांत मंत्री लाल मणि तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर बुधवार को प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने *गाय नहीं कटने देंगे–देश नहीं बंटने देंगे, कटती गऊएं करें पुकार–बंद करो यह अत्याचार* तथा *गौमाता के सम्मान में–विश्व हिंदू परिषद मैदान में* जैसे नारों के साथ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी नगर को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लाल मणि तिवारी ने कहा कि गोवंश भारतीय संस्कृति, सात्विक ऊर्जा, आर्थिक समृद्धि और आरोग्य का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती गोतस्करी और गौहत्या की घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं, जिसे रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद लगातार अभियान चला रहा है। उन्होंने मांग की कि देशभर में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन गोतस्करी एवं गौहत्या में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

पीएम मोदी ने राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है : संजय सरावगी

पटना (हिंस)। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। यह कालखंड केवल सरकार चलाने का नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण, गरीबों के उत्थान और देश को विश्व पटल पर सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का काल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। *सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास* के मंत्र के साथ सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में करोड़ों गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिला, करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से धुएं से मुक्ति मिली, आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली तथा जनधन खातों के जरिए आर्थिक समावेशन को नई गति मिली। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आधारभूत संरचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। देश में रिकॉर्ड संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, आधुनिक एयरपोर्ट, बंदरगाह और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। भारत की डिजिटल व्यवस्था आज दुनिया के लिए उदाहरण बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ तथा विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है और वैश्विक मंचों पर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया भारत की बात गंभीरता से सुनती है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने कठिन चुनौतियों का मजबूती से सामना किया है। कोरोना महामारी के दौरान गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों तक राहत पहुंचाने का कार्य किया गया। भारत ने न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि अन्य देशों की भी सहायता की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में बिहार को भी विशेष लाभ मिला है। सड़क, रेल, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अनेक विकास परियोजनाओं को गति मिली है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बिहार के करोड़ों नागरिकों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व देशवासियों में विश्वास जगाने वाला रहा है तथा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अंत में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सफल 12 वर्षों के कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत आने वाले समय में विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल होकर विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा।

पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर जनविरोधी नीतियों का आरोप

उदयपुर (हिंस)। पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ए ब्लॉक द्वारा बुधवार को हाथीपोल चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने और आमजन को महंगाई से राहत देने की मांग उठाई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा तथा उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व ए ब्लॉक अध्यक्ष सोमेश्वर मीणा ने किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को जनविरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीवन प्रभावित कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल–डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर एवं छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक ओर देश की जनता बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर जनता की परेशानियां बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आमजन के हितों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी तथा सड़कों से लेकर सदन तक जनता की आवाज बुलंद करती रहेगी। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री दिनेश कुमार दवे ने बताया कि प्रदर्शन में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुरेश श्रीमाली, पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्बिया, प्रदेश महामंत्री गोपाल कृष्ण शर्मा, प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा, प्रदेश सचिव दिनेश श्रीमाली, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शराफत खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, महिला कांग्रेस प्रतिनिधि, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, पार्षद एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पेट्रोल पंपों पर चला निरीक्षण अभियान : 226 पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण में 103 नोजल सीज

जयपुर (हिंस)। प्रदेशभर में उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की सही मात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान विभाग ने 13 मई से 18 मई तक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न जिलों में कुल 226 पेट्रोल पंपों की जांच की गई, जिनमें 110 पेट्रोल पंपों पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई की गई। विभाग के अनुसार निरीक्षण के दौरान अधिकांश पेट्रोल पंप निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए और उपभोक्ताओं को सही मात्रा में ईंधन वितरण होता मिला। हालांकि कुछ मामलों में शॉर्ट डिलीवरी की शिकायतें सामने आईं। विभाग ने बताया कि कई स्थानों पर वितरण में बेहद मामूली अंतर पाया गया, जो तापमान, मशीनों की तकनीकी संवेदनशीलता, कैलिब्रेशन अथवा अन्य परिचालन कारणों से हो सकता है। विशेष अभियान के दौरान 60 प्रकरण शॉर्ट डिलीवरी से संबंधित पाए गए। जांच के दौरान 103 नोजल नियमानुसार सीज किए गए। इसके अलावा 56 मामलों में सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं किए जाने तथा 16 मामलों में अप्रमाणित माप उपकरण उपयोग में लेने की अनियमितता सामने आई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कुल 226 पेट्रोल पंपों में से लगभग 116 पेट्रोल पंप पूरी तरह मानकों के अनुरूप पाए गए। अभियान का उद्देश्य पेट्रोल पंप संचालकों को प्रतिदिन *5 लीटर माप* के माध्यम से स्वयं जांच करने और मशीनों का नियमित रखरखाव एवं कैलिब्रेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना है। विधिक माप विज्ञान विभाग ने कहा कि उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और व्यापारिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार के निरीक्षण अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे।

हिस्ट्रीशीटर पर चला बुलडोजर : जयपुर में दो करोड़ का अवैध कब्जा ध्वस्त

जयपुर (हिंस)। राजधानी में पुलिस–प्रशासन ने हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुहाना थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर शंकर लुहार का करीब 2 करोड़ रुपये कीमत का अवैध कब्जा ध्वस्त कर दिया। आरोपी पिछले 12 से 13 वर्षों से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठा था। पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि बुधवार को मुहाना थाना पुलिस और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की संयुक्त टीम ने डिग्गी रोड स्थित मुहाना मोड़ के पास कार्रवाई की। जेसीबी मशीनों की मदद से कुख्यात हिस्ट्रीशीटर शंकर पुत्र गोपी गाड़िया लुहार द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने करीब 200 वर्ग गज सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर रखा था, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये आंकी गई है। शंकर लुहार क्षेत्र में लोगों को डराकर और धमकाकर दहशत का माहौल बनाए हुए था। विरोध करने वालों के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। पुलिस ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर निकास मार्ग भी बंद कर दिया था, जिससे स्टेट हाईवे पर यातायात प्रभावित हो रहा था और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। कार्रवाई के दौरान पूरे अतिक्रमण को हटाकर रास्ता खुलवाया गया। मुहाना थाने

का हिस्ट्रीशीटर शंकर लुहार के खिलाफ 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ 151/110 सीआरपीसी और 129 बीएनएसएस के तहत 7 इस्तगासे भी न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। वर्ष 2015 में उस पर चोरी और नकबजनी के 10 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2016 में मारपीट का मामला भी सामने आया था। डीसीपी राजर्षि राज ने कहा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ *जीरो टॉलरेंस* नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर आगे भी कुर्की और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी।

मोदी सरकार के 12 साल विकास और सुशासन के स्वर्णिम काल : मदन राठौड़

जयपुर (हिंस)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन, विकास और आत्मनिर्भर भारत के स्वर्णिम काल के रूप में दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में देश ने ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, तकनीक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से आमजन को सीधा लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि भारत ने चंद्रयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष क्षेत्र में नया इतिहास रचा, वहीं ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलों के स्वदेशी निर्माण से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए राठौड़ ने कहा कि न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि केवल भारत के नागरिकों को ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार है और अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करना देशहित में नहीं है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए कहा कि अदालत के फैसले के बाद विपक्ष पूरी तरह पराजित हो गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में भारत ने स्वदेशी वैक्सीन बनाकर दुनिया के सामने अपनी वैज्ञानिक क्षमता साबित की। वहीं मुद्रा योजना और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी *वसुधैव कुटुंबकम* और *सर्वे भवन्तु सुखिन:* की भावना के साथ विश्व को शांति और सहयोग का संदेश दे रहे हैं। साथ ही भाजपा राज्यसभा चुनाव की तैयारियों और *वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान* के तहत जल संरक्षण गतिविधियों को भी व्यापक स्तर पर चला रही है।

बढ़ती मांग के बीच पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति जारी

जयपुर (हिंस)। देशभर सहित राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की मांग में अचानक तेजी आने के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटी हुई हैं। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अपने व्यापक नेटवर्क और 24 घंटे संचालन के जरिए बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने का दावा किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख तथा राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने बताया कि हाल के दिनों में कई राज्यों में मौसमी कृषि गतिविधियों और कटाई कार्यों के चलते पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर अपेक्षाकृत कम कीमत होने के कारण खुदरा ग्राहकों और संस्थागत उपभोक्ताओं का रुझान भी तेजी से बढ़ा है। गुप्ता ने कहा कि तेल कंपनियां अपने टर्मिनल, डिपो, पाइपलाइन, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और खुदरा आउटलेट्स के विशाल नेटवर्क के माध्यम से लगातार आपूर्ति बनाए हुए हैं। आपूर्ति दल, परिवहन नेटवर्क और टर्मिनल संचालन टीमें चौबीसों घंटे काम कर रही हैं, ताकि ईंधन की समय पर सप्लाई और पुन:पूर्ति तय की जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर बाजार में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जा रही है। कंपनियां लगातार स्टॉक की स्थिति की समीक्षा कर रही हैं और बढ़ती मांग को देखते हुए लॉजिस्टिक और वितरण व्यवस्था को मजबूत किया गया है। तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उपभोक्ताओं से सामान्य खरीदारी जारी रखने और अनावश्यक रूप से घबराकर अतिरिक्त खरीदारी नहीं करने की अपील की गई है। मनोज गुप्ता ने नागरिकों से कहा कि ईंधन की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत एजेंसियों एवं तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। विशेषज्ञों के अनुसार इस समय कृषि कार्यों और कटाई सीजन के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल की मांग बढ़ी है।

बिजली, डीजल और जनसमस्याओं पर किसानों व मजदूरों ने किया प्रदर्शन

फतेहाबाद (हिंस)। बिजली की कमी, डीजल के रेटों में बढ़ोतरी सहित अन्य समस्याओं को लेकर सैंकड़ों किसानों और मजदूरों ने बुधवार को पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर फतेहाबाद में रोष प्रदर्शन किया। जिलाभर से आए किसान और मजदूर हिसार रोड स्थित नई सब्जी मंडी में एकत्रित हुए और वहां से रोष मार्च निकालते हुए गगनभेदी नारों के साथ लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन में मुख्य वक्ता के तौर पर संगठन के प्रदेशाध्यक्ष मनदीप नथवान ने शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान ओमप्रकाश हसंगा व मनरेगा मजदूर यूनियन के जिला प्रधान केसर दास ने संयुक्त रूप से की। मंच संचालन किसान नेता महेन्द्र सिंह द्वारा किया गया। मजदूर नेता रोही राम लालवास के नेतृत्व में काफी संख्या में मजदूरों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष मनदीप नथवान ने तीखे तेवरों में कहा कि क्षेत्र का आम नागरिक, किसान और मजदूर वर्ग लंबे समय से अनेक मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन संबंधित विभागों को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत करवाने के बावजूद कोई उचित समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे किसानों की खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा और बीमा राशि प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द जारी की जानी चाहिए। इसके अलावा, क्षेत्र में लगातार बढ़ रही सेम की समस्या उपजाऊ जमीनों को बर्बाद कर रही है, जिसका स्थाई तकनीकी समाधान बेहद जरूरी है। मानसून को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मांग की कि घग्गर नाली एवं ड्रेन की तुरंत सफाई करवाई जाए तथा बांधों को समय रहते मजबूत किया जाए ताकि बरसात के समय फसलों और गांवों को नुकसान से बचाया जा सके।

यूपी में 2027 में मुख्यमंत्री योगी को रिटर्न गिफ्ट देंगे ग्राम प्रधान : अखिलेश सिंह

लखनऊ (हिंस)। उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन ने प्रदेश सरकार का आभार जताया है। राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अखिलेश सिंह ने बुधवार को लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि सरकार ने ग्राम प्रधानों को जो उपहार दिया है, उसका रिटर्न गिफ्ट प्रधानों द्वारा मुख्यमंत्री योगी को विधान सभा चुनाव 2027 में दिया जायेगा। अखिलेश सिंह ने बताया कि राज्य के ग्राम प्रधानों से सीधा संवाद कर उन्हें बताया जायेगा कि आगामी चुनाव तक प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का जो इतिहास यूपी सरकार ने रचा है, उससे प्रधानों की साख बढ़ी है। साथ ही गांवों में विकास कार्यों की निरन्तरता का रास्ता भी साफ हुआ है। 15 दिसम्बर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम उत्कर्ष समारोह में ग्राम प्रधानों से ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने का जो वादा किया था उसे पूरा किया है। उन्होंने सेवाओं के विस्तार का जो गिफ्ट दिया है, ग्राम प्रधान इसका रिटर्न गिफ्ट मुख्यमंत्री को वापस करेंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन की ओर से राज्य, मण्डल, जनपद तथा ब्लाक स्तर पर समारोह का आयोजन कर सरकार का आभार जताएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों की कठिनाइयों के समाधान के लिए संवाद जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री से लेकर, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद से मिलकर ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की मांग रखी थी। हमारी मांग को पूरा करके सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह ग्राम प्रधानों के साथ हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए संगठन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया गया।

विश्व शांति के लिए हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ

जोधपुर (हिंस)। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर विश्व शांति, मानव कल्याण एवं आध्यात्मिक जागृति के उद्देश्य से विश्वव्यापी सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ एवं श्रीराम नाम जप का आयोजन महंत परमहंस डॉ. रामप्रसाद महाराज के सान्निध्य में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉ. प्रभात माथुर एवं बृजेश नेपालिया ने बताया कि बड़ा रामद्वारा के परमहंस रामप्रसाद महाराज के मार्गदर्शन में चल रहे इस आध्यात्मिक अभियान से देश–विदेश के अनेक मंदिर, मठ, धार्मिक एवं सामाजिक संगठन जुड़े। इस दौरान सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, श्रीराम नाम जप, दीप प्रज्ज्वलन एवं विश्व शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। इंजीनियर निर्मल कुमार माथुर ने बताया कि भारत में जोधपुर सहित जयपुर, उदयपुर, बेंगलुरू, मुंबई, कोयंबटूर, हैदराबाद, इंदौर, सूरत, पुणे एवं अहमदाबाद सहित विश्व के अनेक देशों जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं मलेशिया में भी इस आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया।

विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस

स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम संबंधित समस्याओं पर बात

वाराणसी (हिंस)। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को महेंद्र इंस्टीट्यूट, दुर्गाकुंड में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम साथिया केंद्र (ओपीडी 201), चिकित्सा विज्ञान संस्थान, सर सुंदरलाल अस्पताल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया। जागरूकता कार्यक्रम का थीम मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा एचपीवी टीकाकरण रहा, जिसमें संसाधन व्यक्ति के रूप में आईएमएस बीएचयू के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रो. डॉ. ममता उपस्थित रहीं। यह कार्यक्रम विभागाध्यक्ष एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडोलसेंट हेल्थ एंड डेवलपमेंट की नोडल अधिकारी प्रो. (डॉ.) संगीता राय के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 80 से अधिक किशोरियों, युवतियों, शिक्षिकाओं एवं स्टाफ ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में डॉ. ममता ने मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के महत्व तथा सैनिटरी पैड के सही उपयोग एवं निपटान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मासिक धर्म से जुड़े आम मिथकों को दूर किया तथा अनियमित

मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं पर बात करते हुए प्रतिभागियों को समय पर नजदीकी स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही उन्होंने किशोरियों को पीसीओएस और पीसीओडी जैसी स्थितियों से बचाव के लिए जीवनशैली में आवश्यक बदलावों के बारे में भी बताया। चर्चा में एचपीवी एवं सर्वाइकल कैंसर से बचाव में एचपीवी टीकाकरण के महत्व पर भी विस्तृत जानकारी दी गई।

इबोला संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट सदर अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार

किशनगंज (हिंस)। विश्व के विभिन्न देशों में इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए किशनगंज जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। केंद्र सरकार और राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की ओर से जारी स्वास्थ्य सलाह के बाद जिले में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। संभावित संक्रमण से निपटने के लिए सदर अस्पताल में 10 शैय्याओं का विशेष पृथकवास केंद्र तैयार किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के मामलों में वृद्धि की जानकारी दिए जाने के बाद भारत सरकार ने सभी राज्यों और जिलों को सतर्क रहने का निर्देश जारी किया है। इसी के तहत किशनगंज में भी स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। सिविल सर्जन डॉ. राज कुमार चौधरी ने बताया कि इबोला जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए सदर अस्पताल में विशेष आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यहां संदिग्ध मरीजों को अलग रखकर चिकित्सकीय निगरानी और उपचार की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों को आवश्यक संसाधन और सुरक्षा उपकरण तैयार रखने का निर्देश

दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तेज बुखार, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, त्वचा पर दाने, लाल आंखें तथा हाल की यात्रा का इतिहास रखने वाले व्यक्तियों की विशेष निगरानी की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण की पहचान, नमूना संग्रह, रोगी स्थानांतरण और संक्रमण नियंत्रण संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। नेपाल सीमा से सटे किशनगंज जिले में सीमावर्ती इलाकों और प्रवेश स्थलों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। बाहर से आने वाले लोगों की पहचान, स्वास्थ्य जांच और यात्रा विवरण की समीक्षा की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पृथकवास में रखने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। जिला एवं प्रखंड स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल को सक्रिय कर दिया गया है। इसके साथ ही आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी संदिग्ध लक्षण दिखाई देने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जिले में किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

पांच जून को लान्च होगा हेक्सागान न्यूट्रिशन का आईपीओ
12 जून को बीएसई और एनएसई पर हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली

न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी हेक्सागान न्यूट्रिशन ने अपने आईपीओ को लान्चिंग का ऐलान कर दिया है। कंपनी का 138.87 करोड़ रुपये का आईपीओ पांच जून को खुलेगा। इस आईपीओ में निवेशक नौ जून तक बोली लगा सकेंगे। एंकर इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में चार मार्च को बोली लगाएंगे। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 10 जून को शेयरों का अलाटमेंट किया जाएगा, जबकि 11 जून को अलाटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 12 जून को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 42 रुपये से लेकर 45 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 333 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम एक लाट यानी 333 शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे, जिसके लिए उन्हें 14,985 रुपये का निवेश करना होगा। इसी तरह रिटेल इनवेस्टर्स 1,94,805 रुपये के निवेश से अधिकतम 13 लाट में 4,329 शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। इस आईपीओ के तहत एक रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 3,08,59,704 शेयर आफर फार सेल विंडो के जरिये जारी किए जाएंगे। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत हिस्सा और नान इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इस इश्यू के लिए कम्युलेटिव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है। वहीं केफिन टेक्नोलाजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। हेक्सागान न्यूट्रिशन की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 5.82 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 12.21 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 24.38 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी को 27.03 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हो चुका था। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में इसे 281.65 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 304.62 करोड़ और वित्त वर्ष 2024-25 में उछल कर 331.29 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

न्यूज ब्रीफ

उबर और जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने की नई साझेदारी की घोषणा

नई दिल्ली। कैब सेवा कंपनी उबर और जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने नई साझेदारी की घोषणा की है। भारत के तेजी से बढ़ते टैक्सी बाजार के लिए दोनों कंपनियों ने विशेष इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने के उद्देश्य से एक समझौता किया है। हाल ही में यह समझौता मुंबई में जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पार्थ जिंदल और उबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दारा खोसरोशाही के बीच हुआ। इस साझेदारी का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करने में मदद करना है। भारत सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील की थी। ऐसे में उबर और जेएसडब्ल्यू की यह साझेदारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई रफ्तार दे सकती है। उबर पहले से ही भारत के कई बड़े शहरों में टाटा मोटर्स और अन्य फ्लीट आपरेटरों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कारों और टू-व्हीलर्स की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है। अब जेएसडब्ल्यू के साथ यह समझौता कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन नेटवर्क को और मजबूत करेगा। इस डील से जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी भारत में नई हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारें लान्च करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 440 मिलियन डालर निवेश करने की योजना बना चुकी है।

गोयल ने कनाडा के निवेशकों को स्वच्छ ऊर्जा, एआई क्षेत्र में भागीदारी के लिए किया आमंत्रित

नई दिल्ली। तीन दिन के आधिकारिक दौरे पर कनाडा गए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को वहां प्रमुख पेंशन कोष, सावरेन और संस्थागत निवेशकों के साथ बैठकें कीं। गोयल ने इन बैठकों में निवेशकों को भारत के साथ स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम मेधा (एआई) डिजिटल ढांचे और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भागीदारी का न्योता दिया। बैठक में गोयल ने सतत विकास और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय बाजारों में सहयोग को और गहरा करने के अवसरों की तलाश करने का भी आह्वान किया। गोयल ने कहा कि विशेष रूप से सनलाइफ फाइनेंशियल के प्रमुख केविन स्ट्रेन के साथ हुई बैठक में बीमा, सेवानिवृत्ति समाधान, स्वास्थ्य वित्तपोषण और भारत के तेजी से बढ़ते वित्तीय सेवा क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई। कई प्रमुख कारोबारी दिग्गजों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंगस के वी प्रेम वत्स, मनुलाइफ फाइनेंशियल कारपोरेशन के अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) फिलिप विदरिंगटन, सनलाइफ कनाडा के अध्यक्ष और सीईओ केविन स्ट्रेन, टोरंटो डोमिनियन बैंक समूह के अध्यक्ष और सीईओ रेमंड चुन, नियो परफार्मेंस मैटिरियल्स के अध्यक्ष और सीईओ रहीम सुलेमान और मैक्केन फूड्स के अध्यक्ष और सीईओ मैक्स कोइयून शामिल रहे।

बायजू के संस्थापक रवींद्रन को बड़ा झटका, सिंगापुर की अदालत ने अवमानना के आरोप में सुनाई छह महीने की जेल

नई दिल्ली। भारत की कभी सबसे सफल मानी जाने वाली एडटेक कंपनी बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटनाक्रम में सिंगापुर की एक अदालत ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी मानते हुए छह महीने जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला रवींद्रन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो पहले से ही भारी आर्थिक संकट और विदेशी निवेशकों के कानूनी दावों का सामना कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों हुई सजा यह पूरा मामला रवींद्रन की संपत्तियों और अदालती आदेशों की अनदेखी से जुड़ा हुआ है। सिंगापुर की अदालत ने स्पष्ट किया है कि रवींद्रन ने अप्रैल 2024 से अपनी संपत्तियों से संबंधित कई अदालती आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की है। इन आदेशों का पालन न करने के कारण ही उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया और छह महीने की जेल की सजा तय की गई। सजा के अलावा, अदालत ने रवींद्रन पर आर्थिक दंड भी लगाया है। उन्हें कानूनी खर्च के तौर पर 90,000 सिंगापुर डालर (लगभग 70,500 अमेरिकी डालर) का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

भारत का इलेक्ट्रानिक्स सपना, क्या चीन की बाधा से रुकेगी रफ्तार

500 अरब डालर के उत्पादन लक्ष्य पर मंडराया संकट, एप्पल की निर्भरता भी चुनौती

नई दिल्ली

मोबाइल और इलेक्ट्रानिक्स कंपनियों के प्रमुख संगठन इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रानिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने भारत की महत्वाकांक्षी चाइना प्लस वन' रणनीति पर चीन के नए नियमों से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर सरकार से तत्काल एक बड़ा अंतर-मंत्रालयी समूह गठित करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि चीन के हालिया फैसले कंपनियों की वैश्विक सप्लाई चेन और कारोबारी विविधीकरण की योजनाओं को बाधित कर सकते हैं, जिससे भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण और निर्यात लक्ष्यों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। आईसीईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले हफ्ते कैबिनेट सचिव को इस संबंध में एक विस्तृत पत्र लिखा है। इसके अनुसार चीन ने अप्रैल में दो नए नियम लागू किए हैं, जो कंपनियों के डेटा इस्तेमाल, सप्लाई चेन बदलने और कारोबार दूसरे देशों में शिफ्ट करने पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित करते हैं। इन नियमों का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यदि कोई चीनी कंपनी भारत में फैक्टरी लगाने या अपने कारोबार को चीन से बाहर शिफ्ट करने का निर्णय लेती है, तो उसके अधिकारियों पर व्यक्तिगत कार्रवाई भी हो सकती है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कोरोना महामारी के बाद दुनियाभर की कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करते हुए भारत जैसे वैकल्पिक विनिर्माण हब की तलाश में हैं, जिसे चाइना प्लस वन रणनीति के नाम से जाना जाता है। भारत इस रणनीति का बड़ा लाभार्थी बनना चाहता है, खासकर मोबाइल और इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर में।

संगठन ने चिंता जताई है कि चीन के ये नियम भारत में विदेशी निवेश के प्रवाह, सप्लाई चेन के विविधीकरण और घरेलू विनिर्माण की गति को गंभीर रूप से बाधित कर सकते हैं। आईसीईए ने सरकार से आग्रह किया है कि विभिन्न मंत्रालयों को मिलकर इन नियमों के दीर्घकालिक असर का गहन अध्ययन करना चाहिए और इनसे निपटने के लिए आवश्यक नीतिगत उपाय करने चाहिए। इलेक्ट्रानिक्स अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर बन चुका है, और वित्त वर्ष 2026 में इसका कुल कारोबार 150 अरब डालर और एक्सपोर्ट 28 अरब डालर तक पहुंचने का अनुमान है। सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन को 500 अरब डालर और एक्सपोर्ट को 200 अरब डालर तक पहुंचाना है।

भारत से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट मोबाइल फोन का होता है। वित्त वर्ष 2026 में मोबाइल फोन उत्पादन 70 अरब डालर और एक्सपोर्ट 29.4 अरब डालर रहा, जिसमें एप्पल का योगदान सर्वाधिक रहा। एप्पल ने अकेले वित्त वर्ष 2026 में भारत से 21 अरब डालर से अधिक के आईफोन एक्सपोर्ट किए, लेकिन कंपनी अभी भी अपने कई प्रमुख पुर्जों के लिए चीन पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर है। यही निर्भरता चीन के नए नियमों को और भी संवेदनशील बनाती है, क्योंकि ये नियम चीनी आपूर्तिकर्ताओं को भारत जैसे बाजारों में विनिर्माण विस्तार से रोक सकते हैं, जिससे चाइना प्लस वन का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हो जाएगा और भारत के निर्यात महत्वाकांक्षाओं पर सीधा असर पड़ेगा।

ग्राहक तेजी से आटोमैटिक कारों की ओर कर रहे हैं रुख

नई दिल्ली। आसान ड्राइविंग और बार-बार गियर बदलने की झंझट से राहत मिलने के कारण लोग तेजी से आटोमैटिक कारों की ओर रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत में आटोमैटिक कारों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे कार का गियरबाक्स खराब हो सकता है और भारी खर्च उठाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, सबसे बड़ी गलती चलती कार में गियर बदलना है। कई लोग कार पूरी तरह रोके बिना ड्राइव मोड से रिवर्स या पार्क मोड में शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा करने से गियरबाक्स के अंदरूनी हिस्सों पर भारी दबाव पड़ता है और इसके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए गियर बदलने से पहले कार को पूरी तरह रोकना जरूरी है। ढलान या फ्लाईओवर से उतरते समय कार को न्यूट्रल मोड में डालना भी नुकसानदायक माना जाता है। कई लोग माइलेज बचाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन इससे कार पर नियंत्रण कम हो जाता है और गियरबाक्स तक आयल सप्लाई प्रभावित होती है। इससे गियर के पुर्जे गर्म होकर जल्दी खराब हो सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर बार-बार पार्क मोड का इस्तेमाल करना भी सही नहीं माना जाता। पार्क मोड केवल गाड़ी खड़ी करने के लिए होता है। ट्रैफिक में लगातार इसका उपयोग करने से लाकिंग पिन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में ब्रेक दबाकर रखना या न्यूट्रल मोड का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है। कार पार्क करते समय सीधे पार्क मोड लगाने की बजाय पहले न्यूट्रल में लाकर हैंडब्रेक लगाना चाहिए।

बड़े बैंकों की चमक फीकी, छोटे बैंक बने निवेशकों की पसंद

बंधन, आरबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने चौंकाया, बढ़ा निवेशकों का भरोसा

नई दिल्ली

भारतीय बैंकिंग सेक्टर चौथी तिमाही के नतीजों के बाद एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। जहां एक ओर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जैसे दिग्गज बैंक निवेशकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाए, वहीं बंधन बैंक, आरबीएल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे छोटे और मझोले खिलाड़ी निवेशकों की नई पसंद बनकर उभर रहे हैं।

मार्जिन पर बढ़ता दबाव और जमा जुटाने की बढ़ती लागत ने बड़े बैंकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जबकि भू-राजनीतिक अनिश्चितता और आगामी नियामक बदलाव भी सेक्टर के लिए नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। ऐसे में निवेशक अब केवल बड़े नामों पर नहीं, बल्कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों और नियामक सुधारों के बीच उभरने वाले नए अवसरों पर भी ध्यान दे रहे हैं।

चौथी तिमाही के नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा मार्जिन और डिपाजिट ग्रोथ की रही। बैंकों को अब ग्राहकों से ज्यादा ब्याज देकर जमा पूंजी जुटानी पड़ रही है, जिससे उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है। यह दबाव खास तौर पर बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंकों में देखा गया, जिसके चलते उनके शेयर बाजार में दबाव में दिखे। एंटीक स्टाक ब्रोकिंग की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितता का असर भी भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर दिख रहा है, जो मार्जिन संबंधी चुनौतियों को और बढ़ा रहा है।

सरकारी बैंकों पर दोहरी मार और भविष्य की चुनौतियां: सरकारी बैंकों पर मार्जिन संबंधी दबाव का असर ज्यादा गहरा दिखा, क्योंकि उनकी ट्रेजरी इनकम भी कमजोर रही। बान्ड यील्ड बढ़ने की वजह से कई बैंकों को ट्रेडिंग लास उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, आने वाले समय में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लास (ईसीएल) फ्रेमवर्क लागू होने और वेतन संशोधन का दबाव भी इन बैंकों की कमाई को प्रभावित कर सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद, सरकारी बैंकों में एसबीआई को बाकी बैंकों के मुकाबले बेहतर स्थिति में माना गया है, जो उसकी मजबूत बैलेंस शीट और बाजार हिस्सेदारी को दर्शाता है।

अंडरडाग से आउटपरफार्मर बनने की राह: जहां दिग्गज बैंक संघर्ष कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे बैंक जिनमें पहले दिक्कतें ज्यादा थीं, अब निवेशकों की पसंद बनते नजर आ रहे हैं। बंधन बैंक में एसेट क्वालिटी को लेकर चिंता कम हुई है, जबकि आरबीएल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। बाजार को लग रहा है कि इन बैंकों में आने वाले समय में मजबूत सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि बड़े बैंकों की तुलना में इन बैंकों में जोखिम ज्यादा माना जाता है, लेकिन मजबूत ग्रोथ की उम्मीद और आकर्षक वैल्यूएशन के कारण इनमें दिलचस्पी बढ़ रही है।

डस्टर का नया पिकअप अवतार नियाग्रा जल्द होगा पेश

नई दिल्ली। रेनाल्ट कंपनी ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी डस्टर के नए पिकअप अवतार नियाग्रा की पहली आधिकारिक झलक पेश की है, जिसने आटोमोबाइल प्रेमियों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। लंबे समय से चर्चा में रहे इस माडल को आधुनिक तकनीक और मजबूत डिजाइन के साथ तैयार किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य उन ग्राहकों को आकर्षित करना है जो एसयूवी जैसी आरामदायक ड्राइविंग के साथ पिकअप वाहन की उपयोगिता भी चाहते हैं। कंपनी आगामी 10 सितंबर को इस वाहन का आधिकारिक अनावरण करेगी। शुरुआती चरण में इसका निर्माण अर्जेंटीना में किया जाएगा और सबसे पहले इसे दक्षिण अमेरिकी बाजारों में उतारा जाएगा। यह पिकअप पारंपरिक भारी-भरकम ट्रकों की तरह लैडर-फ्रेम चेसिस के बजाय मोनोकाक प्लेटफार्म पर आधारित होगा। इससे इसमें एसयूवी जैसी आरामदायक सवारी मिलने की उम्मीद है, जो इसकी एक बड़ी खासियत है। जारी टीजर में वाहन के पिछले हिस्से की झलक दिखाई गई है, जहाँ बड़े अक्षरों में नियाग्रा लिखा नजर आता है और एक उपयोगी ड्राप-डाउन टेलगेट भी दिया गया है। इंजन विकल्पों में टर्बो पेट्रोल और हाइब्रिड पावरट्रेन की उम्मीद है, साथ ही बेहतर आफ-रोड क्षमता के लिए उन्नत फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया जा सकता है।

सर्राफा बाजार में सस्ता हुआ सोना, चांदी में बदलाव नहीं

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सोने के भाव में कमजोरी का रुख नजर आ रहा है। हालांकि चांदी के भाव में लगातार दूसरे दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। सोने की कीमत में आई कमजोरी के कारण देश के ज्यादातर हिस्सों में ये चमकीली धातु 470 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 510 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ती हो गई है।

भाव में आई गिरावट के कारण देश के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,58,880 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,60,680 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,45,640 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,47,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। दूसरी ओर, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में भी 2,84,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ही बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,59,030 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,790 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,58,880 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,45,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,58,930 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,690 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,60,680 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,47,290 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,58,880 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,45,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,930 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,45,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,59,030 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,45,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,930 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,45,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,59,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,45,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद हुए। डाउ जान्स फ्यूचर्स भी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के कारोबार के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। इसी तरह एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है।

अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान सेमीकंडक्टर स्टाक्स में आई तेजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से मिल रही सकारात्मक खबरों के कारण एस एंड पी 500 इंडेक्स और नैस्डेक रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचने में सफल रहे। एस एंड पी 500 इंडेक्स 0.61 प्रतिशत की मजबूती के साथ 7,519.12 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 312.21 अंक यानी 1.19 प्रतिशत की उछाल के साथ 26,656.18 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। दूसरी ओर, डाउ जान्स इंडस्ट्रियल एवरेज 118.02 अंक यानी 0.23 प्रतिशत टूट कर 50,461.68 अंक के स्तर पर आ गया। वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 50,520.20 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार होता रहा। एफटीएसई इंडेक्स 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 10,491.39 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसके विपरीत सीएसी इंडेक्स ने 1.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8,173.11 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसी तरह डीएएक्स इंडेक्स 204.21 अंक यानी 0.81 प्रतिशत फिसल कर 25,184.89 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के नौ बाजार में से पांच के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि चार सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.83 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 5,028.80 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह हैंग सेंग इंडेक्स 219.45 अंक यानी 0.86 प्रतिशत टूट कर 25,380 अंक के स्तर पर आ गया है। जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल यह सूचकांक 1.24 प्रतिशत लुढ़क कर 6,130.19 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.11 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,099.23 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

दूसरी ओर, गिफ्ट निफ्टी 0.21 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,963 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह निक्केई इंडेक्स 636.91 अंक यानी 0.98 प्रतिशत उछल कर 65,633 अंक के स्तर पर आ गया है। कोस्पी इंडेक्स ने बड़ी छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 370.82 अंक यानी 4.61 प्रतिशत की उछाल के साथ 8,418.33 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह ताइवान वेटेड इंडेक्स 1,186 अंक यानी 2.72 प्रतिशत की मजबूती के साथ 44,711.37 अंक के स्तर पर आ गया है। इसके अलावा सेट कंपोजिट इंडेक्स 1.45 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,575.84 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

नार्वे शतरंज 2026 : प्रज्ञानानंद को फिरोजा ने हराया, दिव्या देशमुख ने हम्पी को दी मात

दूसरे दौर में भी दिखा रोमांच, अलिरेजा फिरोजा लगातार दूसरी क्लासिकल जीत के साथ शीर्ष पर मजबूत

ओस्लो (नार्वे)

नार्वे शतरंज 2026 के दूसरे दौर में मंगलवार को एक बार फिर रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिलाड़ियों ने शानदार संघर्ष किया और कई मुकाबलों का फैसला आर्मगेडन टाईब्रेक में हुआ। दूसरे दौर का एकमात्र क्लासिकल मुकाबला फ्रांस के ग्रैंडमास्टर अलिरेजा फिरोजा ने भारतीय स्टार आर. प्रज्ञानानंद के खिलाफ जीता। मुकाबले में फिरोजा ने मिडिल गेम के बाद धीरे-धीरे दबाव बनाया और सटीक खेल के दम पर लगातार दूसरी क्लासिकल जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ उन्होंने अंक तालिका में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली।

कार्लसन ने आर्मगेडन में कीमर को हराया – विश्व नंबर-1 मैग्नस कार्लसन और जर्मनी के शीर्ष खिलाड़ी विन्सेंट कीमर के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला क्लासिकल प्रारूप में ड्रा रहा। कार्लसन लंबे समय तक बढ़त बनाते नजर आए, लेकिन कीमर ने कठिन स्थिति में शानदार बचाव करते हुए मुकाबला बराबरी पर समाप्त किया। हालांकि, आर्मगेडन टाईब्रेक में कार्लसन ने जीत हासिल कर अतिरिक्त अंक अपने नाम किए।

गुकेश को वेस्ली सो ने आर्मगेडन में हराया – विश्व चैम्पियन डी. गुकेश और अमेरिका के वेस्ली सो के बीच भी लंबा रणनीतिक मुकाबला ड्रा रहा। इसके बाद खेले गए आर्मगेडन मुकाबले में वेस्ली सो ने जीत दर्ज कर अतिरिक्त अंक हासिल किए।

महिला वर्ग में बिबिसारा असाउबायेवा कायम रहीं शीर्ष पर – नार्वे शतरंज महिला वर्ग में भी दूसरा दौर बेहद रोमांचक रहा। तीनों क्लासिकल मुकाबले ड्रा रहे और सभी का फैसला आर्मगेडन में हुआ। टूर्नामेंट की शीर्ष खिलाड़ी बिबिसारा असाउबायेवा ने चीन की झू जिनर को आर्मगेडन में हराकर अपनी बढ़त बरकरार रखी। कजाखस्तान की इस ग्रैंडमास्टर ने तेज समय नियंत्रण में शानदार खेल दिखाया।

दिव्या देशमुख ने हम्पी को हराया – भारतीय खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबले में दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को आर्मगेडन टाईब्रेक में पराजित किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच क्लासिकल मुकाबला ड्रा रहा था, लेकिन निर्णायक मुकाबले में दिव्या ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की।

न्यूज ब्रीफ

यूनिटी कप फुटबाल में 27 मई को भारत का मुकाबला जमैका से होगा, 24 साल बाद इंग्लैंड में अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलेगी भारतीय टीम

लंदन। भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबाल टीम आजकल यूनिटी कप 2026 में भाग लेने इंग्लैंड गयी हुई है। भारतीय टीम यहां अपना पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार 27 मई की रात को दूसरे सेमीफाइनल में जमैका से खेलेगी। ये 24 साल बाद पहला अवसर है जब भारतीय टीम इंग्लैंड की धरती पर कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलेगी। इससे पहले आखिरी बार भारतीय फुटबाल टीम ने साल 2002 में इंग्लैंड में मैच खेला था। ऐसे में इस मैच को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। फीफा रैंकिंग में अभी भारतीय टीम 136वें स्थान पर है, जबकि जमैका 71वें स्थान पर है। वहीं, पहले सेमीफाइनल में नाइजीरिया और जिम्बाब्वे की टीमें टकरायेंगी। नाइजीरिया की टीम फीफा रैंकिंग में 26वें स्थान पर एक मजबूत दावेदार है, जबकि जिम्बाब्वे 130वें नंबर पर मौजूद है। इस टूर्नामेंट का प्रारूप ऐसा है कि सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमें तीसरे स्थान के लिए भी प्ले-आफ मैच खेलेंगी, जिससे सभी टीमों को कम से कम दो अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका मिलेगा। सभी मुकाबले लंदन के द वैली स्टेडियम में खेले जाएंगे। ऐसे में भारतीय टीम के लिए यह इंग्लैंड में अपनी क्षमताओं को साबित करने और अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

टी20 में दोहरा शतक लगाना चाहते हैं वैभव सूर्यवंशी, गेल का 175 रनों का रिकार्ड तोड़ना भी है लक्ष्य

मुम्बई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस सत्र में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से कई नये रिकार्ड बनाने वाले राजस्थान रायल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का लक्ष्य अब टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक लगाना है। 15 साल की उम्र में ही इस सत्र में 500 से अधिक रन बनाकर आरेंज कैप के दावेदारों में शामिल वैभव का कहना है कि वह वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल का 175 रनों का रिकार्ड भी तोड़ना चाहते हैं। वैभव ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन के एक शो में ये बातें कहीं। जब पीटरसन ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अर्धशतक का जश्न मनाना अच्छा लगता है तो वैभव का जवाब था, मुझे 50 रन का जश्न मनाना ज्यादा पसंद नहीं है। मैं टी20 में 200 रन बनाना चाहता हूं। मैं गेल का रिकार्ड तोड़ना चाहता हूं। उनका ये बयान सोशल मीडिया में छा गया है। गौरतलब है कि गेल ने आईपीएी 2013 में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए पुणे वारियर्स इंडिया के खिलाफ मात्र 66 गेंदों में नाबाद 175 रन बनाए थे। इस पारी में गेल ने 13 चौके और 17 छक्के लगाये थे, और इसी मैच में उन्होंने 30 गेंदों में लीग का सबसे तेज शतक भी जड़ा था। ये रिकार्ड आज भी बरकरार है। वहीं वैभव इस सत्र के सबसे बड़े युवा सितारे बनकर उभरे हैं। उन्होंने 14 मैचों में 41.64 की शानदार औसत और 232.27 की विस्फोटक स्ट्राइक रेट से कुल 583 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा है। इस सीजन में उन्होंने 53 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा हैं। वह क्रिस गेल के 59 छक्कों के रिकार्ड से सिर्फ 7 छक्के दूर हैं जो इसी सत्र में हासिल कर सकते हैं। वैभव टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। वैभव ने इस साल अंडर-19 विश्व कप में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर 7 मैचों में 439 रन बनाए थे।

आईपीएल से लौटे माधव तिवारी मध्य प्रदेश लीग के लिए उज्जैन फाल्कन्स से जुड़े

उज्जैन (मध्य प्रदेश)। मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी-20 सिंधिया कप 2026 से पहले उज्जैन फाल्कन्स को बड़ी मजबूती मिली है। आलराउंडर माधव तिवारी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स का अभियान समाप्त होने के बाद उज्जैन फाल्कन्स कैंप से जुड़ गये हैं। उज्जैन फाल्कन्स अपनी एमपीएल टी-20 अभियान की शुरुआत 3 जून को इंदौर के प्रतिष्ठित होलकर स्टेडियम में ग्वालियर चीताज के खिलाफ करेगी। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले आलराउंडर माधव ने आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए तीन मुकाबले खेले और प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए चार विकेट हासिल किए। टीम ने पूर्व मध्य प्रदेश क्रिकेटर सुनील धोलपुरे के मार्गदर्शन में टूर्नामेंट की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं, जहां खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ लगातार अभ्यास सत्रों में हिस्सा ले रहे हैं। रविवार को आयोजित एक भव्य समारोह में उज्जैन फाल्कन्स की नई जर्सी का भी आधिकारिक अनावरण किया गया था, जो उज्जैन की संस्कृति, पहचान और जोश को दर्शाती है। माधव तिवारी के टीम से जुड़ने पर उज्जैन फाल्कन्स के प्रमोटर विनायक कालानी ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ शानदार आईपीएल सीजन बिताने वाले माधव तिवारी का हम उज्जैन फाल्कन्स परिवार में स्वागत करते हैं।

एफआईएच प्रो लीग : हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम घोषित, यूरोपीय दौरे पर पाकिस्तान-इंग्लैंड से भिड़ेगा भारत

हाकी इंडिया ने 24 सदस्यीय मजबूत टीम का किया ऐलान, विश्व कप तैयारियों पर फोकस

नई दिल्ली

हाकी इंडिया ने बुधवार को एफआईएच प्रो लीग 2025-26 के यूरोपीय चरण के लिए 24 सदस्यीय भारतीय पुरुष हाकी टीम की घोषणा कर दी। स्टार डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह व्यक्तिगत कारणों से फरवरी में होबार्ट चरण से बाहर रहने के बाद टीम में वापसी करते हुए एक बार फिर कप्तानी संभालेंगे।

भारतीय टीम इस दौरे के दौरान नीदरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों से भिड़ेगी। यह दौरा आगामी हाकी विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बेल्जियम में तैयारी, फिर नीदरलैंड और इंग्लैंड में मुकाबले

भारतीय टीम 7 से 9 जून तक बेल्जियम के ब्रुसेल्स में तैयारी शिविर और अभ्यास मैच खेलेगी। इसके बाद टीम 10 जून से नीदरलैंड के राटरडैम में रहेगी, जहां प्रो लीग मुकाबले खेले जाएंगे। राटरडैम चरण के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के लंदन जाएगी, जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले होंगे।

अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण

टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं का संतुलित मिश्रण रखा गया है। चयनकर्ताओं ने आगामी विश्व कप को ध्यान में रखते हुए कोर टीम को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। रक्षा पंक्ति में कप्तान हरमनप्रीत सिंह के साथ अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंह, जुगराज सिंह और युवा खिलाड़ी अमनदीप लकड़ा शामिल हैं। मिडफील्ड की जिम्मेदारी हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद और राज कुमार पाल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों पर होगी। आक्रमण में मनदीप सिंह, सुखजीत सिंह, अभिषेक और सेल्वम कार्थी जैसे तेजतर्रार फारवर्ड टीम की ताकत होंगे।

पांच स्टैंडबाय खिलाड़ी भी घोषित

हाकी इंडिया ने पांच स्टैंडबाय खिलाड़ियों की भी घोषणा की है। इनमें गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक, फारवर्ड अराइजीत सिंह हुंडाल और मनिंदर सिंह, डिफेंडर पूवन्ना चंदूरा बाबी तथा मिडफील्डर विष्णु कांत सिंह शामिल हैं।

कोच क्रेग फुल्टन बोले – विश्व स्तरीय टीमों के खिलाफ खुद को परखने का शानदार मौका

मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने कहा, टीम का प्रशिक्षण शानदार चल रहा है और खिलाड़ी बेहतरीन लय में हैं। जून में नीदरलैंड और इंग्लैंड में होने वाले प्रो लीग मुकाबले हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। विश्व स्तरीय टीमों के खिलाफ ये मुकाबले बताएंगे कि विश्व कप की तैयारियों में हम कहां खड़े हैं।

भारतीय टीम

गोलकीपर: मोहित होन्नेनहल्ली शशिकुमार, सूरज करकेरा

डिफेंडर: हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, सुमित, संजय, यशदीप सिवाच, अमनदीप लकड़ा, जरमनप्रीत सिंह, जुगराज सिंह

मिडफील्डर: हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, नीलकांत शर्मा, विवेक सागर प्रसाद, रबीचंद्र सिंह मोइरांगथेम

फारवर्ड: मनदीप सिंह, सुखजीत सिंह, अभिषेक, आदित्य अर्जुन लालगे, दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लकड़ा, सेल्वम कार्थी

भारत के मुकाबलों का कार्यक्रम (भारतीय समयानुसार)

राटरडैम, नीदरलैंड:

- 14 जून: नीदरलैंड बनाम भारत — शाम 7:30 बजे
- 17 जून: भारत बनाम जर्मनी — रात 11:00 बजे
- 18 जून: जर्मनी बनाम भारत — रात 11:00 बजे
- 21 जून: नीदरलैंड बनाम भारत — शाम 5:30 बजे

लंदन, इंग्लैंड:

- 23 जून: पाकिस्तान बनाम भारत — शाम 7:00 बजे
- 25 जून: इंग्लैंड बनाम भारत — रात 12:00 बजे
- 26 जून: भारत बनाम पाकिस्तान — रात 10:30 बजे
- 28 जून: इंग्लैंड बनाम भारत — रात 8:30 बजे।

फ्रेंच ओपन 2026: यानिक सिनर ने आसान जीत के साथ दूसरे दौर में बनाई जगह

पेरिस

विश्व नंबर-1 इटली के यानिक सिनर ने फ्रेंच ओपन 2026 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए फ्रांस के क्लेमेंट तबूर को सीधे सेटों में 6-1, 6-3, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया।

दो बार के मौजूदा चैम्पियन कार्लोस अल्काराज चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हैं, ऐसे में सिनर को खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। कोर्ट फिलिप शात्रिए पर खेले गए मुकाबले में सिनर ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और अपने प्रतिद्वंद्वी को संभलने का मौका नहीं दिया।

24 वर्षीय सिनर इस मुकाबले में लगातार 29 मैचों की जीत के साथ उतरे थे। इस दौरान उन्होंने केवल तीन सेट गंवाए थे और इसी महीने सभी मास्टर्स 1000 खिताब पूरे करने की उपलब्धि भी हासिल की थी।

सिनर ने मैच की शुरुआत में ही तबूर की सर्विस तोड़कर 2-0 की बढ़त बना ली। इसके बाद उन्होंने एक और ब्रेक हासिल करते हुए स्कोर 4-1 कर दिया। दमदार फोरहैंड विनर के साथ उन्होंने पहला सेट आसानी से अपने नाम किया।

दूसरे सेट में भी इतालवी खिलाड़ी ने शानदार नियंत्रण बनाए रखा और बिना ज्यादा परेशानी के सेट जीत लिया।

तीसरे सेट में फ्रांसीसी खिलाड़ी क्लेमेंट तबूर ने कुछ बेहतरीन शाट लगाए और घरेलू दर्शकों का भरपूर समर्थन हासिल किया। विश्व रैंकिंग में 171वें स्थान पर मौजूद तबूर ने कुछ समय के लिए सिनर पर दबाव भी बनाया।

हालांकि, सिनर ने जल्द ही मैच पर दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया। उनकी सटीक ग्राउंडस्ट्रोक्स और लगातार आक्रामक खेल के सामने तबूर ज्यादा देर टिक नहीं सके।

जीत के बाद यानिक सिनर ने कहा, मैं यहां वापस आकर बेहद खुश हूं। इस कोर्ट से मेरी कई शानदार यादें जुड़ी हैं। पहले दौर के मुकाबले कभी आसान नहीं होते। उन्होंने फ्रांसीसी दर्शकों का धन्यवाद करते हुए कहा, समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि मैं एक फ्रांसीसी खिलाड़ी के खिलाफ खेल रहा था, फिर भी दर्शकों ने निष्पक्षता दिखाई।

एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप पर हैं मनु की नजरें

नई दिल्ली। ओलंपिक पदक विजेता महिला निशानेबाज मनु आजकल एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों में लगी हैं। मनु का लक्ष्य इन टूर्नामेंटों में बेहतर प्रदर्शन कर पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन चक्र के लिए अपनी दावेदारी पक्की करना है। मनु का कहना है कि अभी उनका ध्यान अपना फार्म बनाये रखते हुए बेहतर प्रदर्शन करने पर है। मनु ने दृढ़ता से कहा, इस साल एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स हमारे सामने हैं, और हम इन दोनों बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कोच के साथ बैठकें की हैं और आगामी टूर्नामेंट्स तथा अपनी तैयारी की एक संपूर्ण और सुनियोजित रूपरेखा तैयार कर ली है। इससे ये साफ है कि उनकी रणनीति केवल तात्कालिक सफलता पर नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि की योजना का हिस्सा है।

रैना ने शुभमन और सुदर्शन की जोड़ी को आईपीएल की सबसे अच्छी जोड़ी बताया

नई दिल्ली

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान शुभमन गिल और सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि इनकी जोड़ी आईपीएल इतिहास की सबसे अच्छी सलामी जोड़ी है। रैना ने कहा कि शुभमन और सुदर्शन ने जिस तेजी और निरंतरता के साथ रन बनाए हैं।

ऐसा करने में कोई भी दूसरी जोड़ी सफल नहीं रही है। इन दोनों ने साथ मिलकर केवल 46 पारियों में ही तेजी से खेलते हुए 21 बार 50 या उससे अधिक रनों की साझेदारी की है। इससे उनकी आपसी समझ और मैदान पर एक दूसरे के साथ अच्छे तालमेल का पता चलता है। रैना ने कहा कि इस जोड़ी ने विराट कोहली और क्रिस बेल के अलावा एबी डिविलियर्स और-विराट की जोड़ी को भी पीदे छोड़ दिया है। रैना ने कहा, जहां गेल और कोहली को 21 बार 50 से अधिक रनों की साझेदारी तक पहुंचने में 59 पारियां लगी थीं, वहीं डिविलियर्स और कोहली ने यह उपलब्धि 76 पारियों में हासिल की थी जबकि शुभमन और सुदर्शन ने यह आंकड़ा केलव 46 पारियों में ही हासिल कर लिया। इन जोड़ी ने आईपीएल के अलावा टी20 क्रिकेट में भी कई बड़े रिकार्ड बनाये हैं। इस जोड़ी ने अब तक 10 शतकीय साझेदारियाँ बनायी हैं, और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह सबसे तेज जोड़ी है। इस जोड़ी ने आईपीएल में बिना कोई विकेट खोये 200 रन के लक्ष्य को भी आसानी से हासिल किया है। इन दोनो ने ही पारी शुरु करते हुए आईपीएल में 2000 से अधिक रन बनाये हैं, और उनकी साझेदारी का औसत 67 से अधिक का है, जो उनकी निरंतरता और एक-दूसरे के प्रति समझ को स्पष्ट रूप से दिखाता है। यह औसत उनकी बल्लेबाजी की गहराई और हर हाल में प्रदर्शन करने की क्षमता भी दिखाता है। रैना के अनुसार, गिल और सुदर्शन की सबसे बड़ी ताकत उनके बीच की अच्छी समझ और फिटनेस है। उन्होंने समझाया, दोनों बल्लेबाज अविश्वसनीय रूप से फिट हैं और उन्हें अच्छी तरह पता है कि कब आक्रामक होना है और किस गेंदबाज को निशाना बनाना है। एक गेंद की गति का इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरा कोण बनाकर शानदार शाट्स खेलता है, जिससे विपक्षी गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना असंभव हो जाता है। इसका भी सबसे बड़ा लाभ टीम को मिला है।

बुमराह को अब भी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मानते हैं एबी डिविलियर्स

जोहांसबर्ग

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खराब प्रदर्शन के बाद निशाने पर आये तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का बचाव किया है। डिविलियर्स ने कहा है कि बुमराह अभी भी विश्वकप के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं और महज एक सत्र खराब होने से उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता है। डिविलियर्स ने माना है कि बुमराह मुंबई इंडियंस की ओर से उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाये हैं पर कहा कि इस प्रकार का खराब दौर हर क्रिकेटर के जीवन में आता है पर इसका कलतब ये नहीं कि वे बेकार हो गये। साथ ही कहा कि इससे उनकी गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता और वह जल्द ही अपने पुराने रंग में लौटेंगे।

बुमराह के लिए यह सत्र बेहद खराब रहा है। पूरे टूर्नामेंट में वह 13 मैच केवस 4 विकेट ही ले पाये। ये उनके जैसे खिलाड़ी के लिए बेहद निराशाजनक है। उनका गेंदबाजी औसत 102.50 रहा, जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक ही टूर्नामेंट में 40 या उससे अधिक ओवर फेंकने वाले गेंदबाज का अब तक का सबसे खराब औसत माना जा रहा है।

डिविलियर्स ने बुमराह का बचाव करते हुए कहा कि एक खराब प्रदर्शन किसी भी खिलाड़ी की क्लास को खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने जोर देकर कहा, यह बुमराह के आईपीएल करियर का सबसे खराब सत्र रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका औसत 100 से ज्यादा रहा, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इन सबके बावजूद, मुझे अब भी लगता है कि वह दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। डिविलियर्स ने बुमराह की क्षमताओं पर अटूट विश्वास व्यक्त किया। साथ ही कहा कि वह जल्द ही अपने पुराने शानदार अंदाज में वापसी करेंगे। यह भी याद रखन चाहिये कि आईपीएल से पहले टी20 विश्व कप में उन्होंने भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

आरसीबी की जीत के बाद विराट, अनुष्का हुए रोमांटिक, प्रशंसक भी उत्साहित दिखे

धर्मशाला। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के पहले क्वालीफायर में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की गुजरात टाइटंस के खिलाफ बड़ी जीत के बाद का एक बेहतरीन वीडियो आया है। इसमें आरसीबी की जीत के बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का रोमांटिक अंदाज देखकर प्रशंसक भी उत्साहित दिखे। आरसीबी ने गुजरात के खिलाफ जीत के साथ ही फाइनल में जगह बनायी है। टीम की इस जीत के बाद विराट और अनुष्का का एक बेहद भावुक और रोमांटिक पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिससे प्रशंसक उत्साहित हैं। गुजरात पर जीत पक्की होने के बाद, विराट स्टैंड्स में अपने परिवार और अनुष्का से मिलने पहुंचे। जैसे ही वे अपनी पत्नी के पास पहुंचे, उन्होंने उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया, जो जादू की झप्पी से कम नहीं थी। इस रोमांटिक और इमोशनल पल को देखकर मैदान में मौजूद प्रशंसक खुशी से झूम उठे और विराट-अनुष्का के नाम के नारे लगाने लगे। अनुष्का अक्सर मैदान पर विराट और उनकी टीम का हौसला बढ़ाने स्टेडियम पहुंचती रहती है। आईपीएल 2026 के इस क्वालिफायर मुकाबले में आरसीबी की जीत के बाद ये दोनो ही बेहद खुश दिखे।

जानें क्या है मयूरासन और इसके लाभ

मयूरासन यानी मयूर की तरह किया जाने वाला आसन। योगा में यह वह आसन है जिसमें आपका शरीर मयूर की तरह दिखाई पड़ता है। इस आसन को करने के लिए बहुत सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। इस आसन में शरीर का पूरा भार हाथों पर टिका होता है और शरीर हवा में लहराता है। मयूरासन के भी कई लाभ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मयूरासन कैसे किया जाए। मयूरासन के लाभ क्या हैं। मयूरासन करने की विधि क्या है। मयूरासन कब करना चाहिए। इत्यादि सवालों के जवाब जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि मयूर आसन क्या है।

मयूरासन करने की विधि

मयूरासन खुली हवादार जगह में करना चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले घुटनों के बल बैठ जाएं और आगे की ओर झुके। आगे झुकते हुए दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़कर नाभि पर लगाकर जमीन पर सटा लें। इसके बाद अपना संतुलन बनाते हुए घुटनों को धीरे-धीरे सीधा करने की कोशिश करें। अब आपका शरीर पूरी सीध में है और सिर्फ आपके हाथ जमीन से सटे हुए हैं। इस आसन को करने के लिए शरीर का संतुलन बनाए रखना जरूरी है जो कि पहली बार में संभव नहीं। यदि आप रोजाना मयूर आसन का अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित तौर पर आसानी से इसे कर पाएंगे।

मयूरासन के दौरान सावधानी

मयूरासन करते हुए बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आप जब भी मयूरासन करें तो किसी योग एक्सपर्ट की देखरेख में करें या फिर पहले इस आसन को करने की विधि को अच्छी तरह से जानें। तभी आप मयूर आसन को सही तरह से कर पाएंगे और इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे।

मयूरासन के लाभ

- मयूरासन के कई लाभ है। आमतौर पर मयूरासन से गुर्दे, अग्नाशय और आमाशय के साथ ही यकृत इत्यादि को बहुत लाभ होता है।
- चेहरे पर चमक लाने के लिए मयूरासन करना चाहिए। मयूरासन करने से हाथ, पैर व कंधे की मांसपेशियों में मजबूती आती है। जिन लोगों को बहुत अधिक कब्ज रहती है उनके लिए मयूरासन से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। मधुमेह के रोगियों के लिए भी यह आसन लाभकारी है।
- यदि आपको आंखों संबंधी कोई समस्या है तो उसका निदान भी मयूरासन से किया जा सकता है।
- पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए मयूरासन करना चाहिए। यदि आपको पेट संबंधी समस्याएं जैसे गैस बनना, पेट में दर्द रहना, पेट साफ ना होना इत्यादि होता है तो आपको मयूरासन करना चाहिए।
- सामान्य रोगों के अलावा मयूर आसन से आंतों व अन्य अंगों को मजबूती मिलती है। मयूरासन से आमाशय और मूत्राशय के दोषों से मुक्ति मिलती है।

किसे नहीं करना चाहिए

- आमतौर पर मयूरासन उन लोगों को करने के लिए मना किया जाता है जो उच्च रक्तचाप की समस्या से पीड़ित हैं।
- टी.बी यानी तपेदिक के मरीजों को भी मयूरासन नहीं करना चाहिए।
- हृदय रोग या हार्ट की बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी मयूरासन नहीं करना चाहिए। अल्सर और हर्निया रोग से पीड़ित लोगों को भी मयूरासन करने से बचना चाहिए।

हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले... आज युवाओं की कई ख्वाहिशें हैं। खासतौर पर युवा आजादी चाहता है। आज के दौर में युवाओं की सोच में क्रांति और आजादी की बातें उभरकर सामने आ रही हैं। आखिर देश का युवा किन बातों से आजादी चाहता है, यही जानने की कोशिश है यह आलेख।

हर ख्वाहिश पर दम निकले...

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला सात महीने में तीसरी बार भारत की विजिट पर आए हैं। वे सोमवार को दिल्ली में माइक्रोसॉफ्ट के इवेंट में ऐड्रेस करने पहुंचे। गालिब के शेर से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जब आप दुनिया को देखने का नजरिया बदल लेते हैं, तो आप दुनिया को भी बदल पाते हैं। एक वाकये का जिक्र करते हुए सत्या ने गालिब का शेर पढ़ा-**हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले।** उनके इस अंदाज पर काफी देर तक हाल तालियों से गूंजता रहा। उन्होंने गालिब का यह शेर जिस भी संदर्भ में सुनाया हो लेकिन यह शेर आज के दौर में देश के युवाओं के लिए कुछ खास है। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी बसती है। इस देश में करीब 30.56 करोड़ युवा बसते तो हैं लेकिन शायद बहुत कम युवाओं की ख्वाहिशें पूरी हो पाती हैं। यहां हम युवाओं की व्यक्तिगत ख्वाहिशों की बात नहीं कर रहे। यहां युवाओं की समग्र ख्वाहिशें हैं। आज देश का युवा आजादी चाहता है। यही उसकी ख्वाहिश है। आइए देखते हैं किन मुद्दों से भारतीय युवा को आजादी चाहिए...

जबरन करियर से आजादी

देश के ज्यादातर युवा इस मुश्किल से जूझ रहे हैं। 18 साल की उम्र तक पहुंचते ही उन पर करियर को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी जाती है और आखिर में उन पर जबरन कुछ भी थोप दिया जाता है। ज्यादातर मां-बाप बच्चे की ख्वाहिश पूछे बिना ही उसे इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए मजबूर करते हैं।

ऑनर किलिंग से आजादी

देश के कई हिस्सों में खाप जैसी पंचायतें के तुगलकी फरमान युवाओं की इच्छा के आड़े आते हैं। खास तौर पर हरियाणा में खाप का असर ज्यादा है। जहां जरा सी बात पर लोग आत्म सम्मान के नाम पर युवक-युवतियों को मार देते हैं। कई मामलों में लड़के लड़की दोनों की हत्या कर दी गई। समलैंगिकता, प्रेम विवाह, अपनी मर्जी से लड़का या लड़की चुनना ये सारी बातें खाप के नियमों के खिलाफ मानी जाती हैं, जिनसे मुक्ति जरूरी है। यही नहीं, पुलिस भी ऐसे कामों में तुगलकी फरमान सुनाती है।

लिंग भेद से आजादी

लिंग भेद से आजादी ऐसी आजादी है जिसके लिए हर लड़की जन्म लेने के साथ ही लड़ना शुरू कर देती है। घर में ज्यादा तवज्जो न मिलने से लेकर अपनी मर्जी के कपड़े न पहन पाने तक, लड़कियों को कई सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। यहां तक कि शादी करने में भी उनकी पसंद का ख्याल नहीं रखा जाता।

अपने नजरिये की आजादी

लोकतंत्र में रहने के चलते हर किसी को अपना नजरिया रखने की आजादी होनी चाहिए लेकिन भारत ऐसा देश है जहां अपनी बात रखना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। सोशल मीडिया ने इस वॉर को और बढ़ाया है। भीड़ से अलग हटकर अगर आप अपना नजरिया पेश करते हैं तो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी या उसके समर्थकों के शिकार बन जाते हैं।

सुरक्षा की चिंता से आजादी

हर मां-बाप अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहते हैं लेकिन वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि घर की चारदीवारी में कैद करके बच्चों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। खासकर लड़कियों के मामले में परिजन ज्यादा सख्त होते हैं। उनके घर से निकलने और घर लौटने के समय को लेकर वो ज्यादा चिंतित होते हैं क्योंकि उन्हें उत्पीड़न, अपहरण या हत्या जैसी वारदातों का डर सताता रहता है।

इस्तेमाल होने से आजादी

हर युवा अपने उज्ज्वल जीवन की ख्वाहिश रखता है। युवा जब देखता है कि केवल योग्यता और ईमानदारी से कार्य संभव नहीं, तो कुंठाग्रस्त होकर गलत रास्तों पर चल पड़ता है। निश्चित तौर पर ऐसे में ही समाज के दुश्मन उनकी भावनाओं को भड़काकर व्यवस्था के विरूद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित करते हैं, फलतः अपराध और आतंकवाद का जन्म होता है। युवाओं को मताधिकार तो दे दिया गया है पर उच्च पदों पर पहुंचने और निर्णय लेने के उनके स्वप्न को दमित करके उनका इस्तेमाल नेताओं द्वारा सिर्फ अपने स्वार्थ में किया जा रहा है।

सब्ज-बाग से आजादी

आज का युवा संक्रमण काल से गुजर रहा है। वह अपने बलबूते आगे तो बढ़ना चाहता है, पर परिस्थितियां और समाज उसका साथ नही देते। चाहे वह राजनीति हो, फिल्म व मीडिया जगत हो, शिक्षा हो, उच्च नेतृत्व हो- हर किसी ने उसे सुखद जीवन के सब्ज-बाग दिखाए और फिर उसको भंवर में छोड़ दिया। ऐसे में पीढ़ियों के बीच जनरेशन गैप भी बढ़ा है। समाज की कथनी-करनी में भी जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ वह सभी को डिग्रीधारी देखना चाहता है, पर उन सभी हेतु रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाता। नतीजन- निर्धनता, महंगाई, भ्रष्टाचार इन सभी की मार सबसे पहले युवाओं पर पड़ती है। इसी प्रकार व्यावहारिक जगत में आरक्षण, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, भाई-भतीजावाद और कुर्सी की लालसा जैसी चीजों ने युवा हृदय को झकझोर दिया है।

दोहरेपन से आजादी

इसमें कोई शक नहीं कि युवा वर्ग ही भावी राष्ट्र की आधारशिला रखता है, पर दु:ख तब होता है जब समाज युवाओं में भटकाव हेतु युवाओं को ही दोषी ठहराता है। क्या समाज की युवाओं के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति जब सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का सरेआम क्षरण करते नजर आते हैं, तो फिर युवाओं को ही दोष क्यों? एक व्यक्ति द्वारा अटपटे बयान देकर या किसी युवती द्वारा अर्धनग्न पोज देकर जो नाम हासिल किया जा सकता है, वह दूर किसी गांव में समाज सेवा कर रहे युवा को तभी मिलता है जब उसे किसी अंतराष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाता है। आखिर ये दोहरापन क्यों?

दोषारोपण से आजादी

युवा व्यवहार मूलतः एक शैक्षणिक, सामाजिक, संरचनात्मक और मूल्यपरक समस्या है जिसके लिए राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सभी कारक जिम्मेदार हैं। ऐसे में समाज के अन्य वर्गों को भी जिम्मेदारियों का अहसास होना चाहिए, सिफ4 युवाओं को दोष देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ युवा शक्ति के भटकाव का नहीं है, वरन अपनी संस्कृति, सभ्यता, मूल्यों, कला एवम् ज्ञान की परंपराओं को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का भी है। युवाओं को भी ध्यान देना होगा कि कहीं उनका उपयोग सिर्फ मोहरों के रूप में न किया जाय।

आधा घंटा बंद रखें स्मार्टफोन...

आज के दौर में स्मार्ट फोन हमारी जरूरत बन गया है। सभी युवाओं के पास स्मार्टफोन मौजूद हैं। इसके कई फायदे भी हैं। स्मार्टफोन से न सिर्फ हमें जरूरी जानकारियां मिल जाती हैं, बल्कि यह मित्रों को भी हमारे साथ जोड़े रखने का काम करता है। स्मार्ट फोन की कई खूबियों के बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं। वहीं इस स्मार्ट फोन के कुछ नुकसान भी हैं। स्मार्टफोन के जानकारों का कहना है कि अगर स्मार्ट फोन को दिन में आधे घंटे भी बंद रखा जाए तो इससे कई सारे फायदे मिल सकते हैं। आज हम आपको इन्हीं फायदों के बारे में बता रहे हैं।

दिमाग को मिलेगा रेस्ट

दिमाग असल में कई कामों को करने में व्यस्त रहता है। इन कामों को करने में वह तेजी से थकता है। ऐसे में आप अपना स्मार्ट फोन करीब आधा घंटा बंद रख सकते हैं। इससे आपके दिमाग को भी रेस्ट मिलेगा और वह भी तेजी से काम कर सकेगा।

ओवरहीटिंग से बचेगा

कई बार हमारा स्मार्ट फोन ओवरहीट हो जाता है। इसके हीट होने के वैसे तो और भी कई कारण हो सकते हैं। आपका फोन जब भी ओवरहीट हो जाए ऐसी स्थिति में आपको इसे कुछ देर के लिए बंद कर देना चाहिए। यही आपके पास पहला विकल्प है। इसके बाद इसकी समस्या को कहीं पर दिखा लीजिए।

समाधान जल्दी

हर समय फोन से चिपके रहने से दिमाग कई तरह की समस्या का समाधान सही तरीके से नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में फोन से थोड़े समय की दूरी बनाना आपके लिए हर समस्या का हल ढूंढने के लिए बेहतर हो सकता है। ब्रेन को आराम मिलने से यह सही ढंग से काम करने के काबिल हो जाता है।

काम में लगता है मन

एक रिसर्च में पाया गया है कि करीब 61 प्रतिशत लोग हर समय नोटिफिकेशन देखते रहते हैं। नोटिफिकेशन न आने की स्थिति में भी लोगों को लगता है कि कोई नोटिफिकेशन आया है। ऐसे में वह व्यक्ति अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता। स्मार्ट फोन को बंद करने से काम पर फोकस हो पाता है और वह अच्छी तरह से किया जाता है।

रीबूट करने का फायदा

स्मार्टफोन कई बार हैंग होने लगता है। कई सारी ऐप्स बैकग्राउंड पर चलने से और मैमोरी ज्यादा यूज होने के कारण फोन हैंग करने लगता है। ऐसी स्थिति में आप अपना फोन रीबूट कर सकते हैं। रीबूट करने से फोन दोबारा से सही चलने लगता है।

दाढ़ी मूंछ के भी हैं ढेरों फायदे

आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन वैज्ञानिक तक मान चुके हैं कि दाढ़ी रखने से त्वचा का कैंसर नहीं होता। दरअसल सूर्य की अल्ट्रावाइलेट किरणें स्किन कैंसर का कारण बनती है। शोध के मुताबिक लोग दाढ़ी रखते हैं वे 90 फीसदी तक यूवी किरणों से अपने आपको बचाने में कामयाब रहते हैं। है ना स्किन कैंसर से बचने का बढ़िया उपाय। क्लीन शेव लोगों की तुलना में दाढ़ी मूंछ रखने वाले लोगों को अस्थमा और एलर्जी की शिकायत कम होती है। दरअसल प्रदूषित होते वातावरण में दाढ़ी मूंछ धूल और प्रदूषण को सीधे चेहरे और मुंह के संपर्क में नहीं आने देती। दाढ़ी और मूंछ के बाल छलनी की तरह काम करके प्रदुषित कणों को रोक लेते हैं। ये ठीक वही काम करती है जो आंखों के लिए पलक और नाक के बाल करते हैं। दाढ़ी मूंछ रखने वालों की स्किन आमतौर पर ड्राई नहीं मिलेगी। दरअसल दाढ़ी मूंछ होने से चेहरे पर रोजमर्रा की फेसक्रीम का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। दाढ़ी मूंछ चेहरे को जवान बनाए रखते हैं क्योंकि इससे त्वचा पर नमी बनी रहती है। दाढ़ी मूंछ रखने वाले लोग चेहरे से आमतौर पर जवान दिखते हैं क्योंकि उनकी दाढ़ी मूंछ उनके चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों को छिपा लेती हैं। रोज रोज शेव करने से स्किन कटने फटने का डर रहता है और त्वचा पर संक्रमण का भी खतरा रहता है लेकिन दाढ़ी मूंछ रखने से ये झंझट और संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता।

ऑनलाइन रहना क्यों पसंद...?

इंटरनेट के माध्यम से अब दुनिया के किसी भी भाग से आसनी से संपर्क बनाया जा सकता है। लोग अब घर बैठे ही दुनियाभर में अपने दोस्त बनाने लगे हैं, और ऑनलाइन रहकर ही प्यार ,डेटिंग, और शादी के लिए जोड़े भी खोजे जाने लगे हैं। ऑनलाइन दोस्ती के बहुत से नुकसान भी होते हैं, जैसे आप जिससे दोस्ती कर रहें हैं वह वास्तव में अपने बारे में सारी बातें सच बता रहा है, या आपको धोखा देने के मकसद से झूठी बातें बता रहा है। आप उसे सामने से नहीं देख सकते इसलिए आप उसकी वास्तविकता भी नही जान सकते हैं। ऑनलाइन चैटिंग से होने वाले इन नुकसानों के बावजूद क्यों हम इसका इस्तेमाल करना जारी रखते हैं?

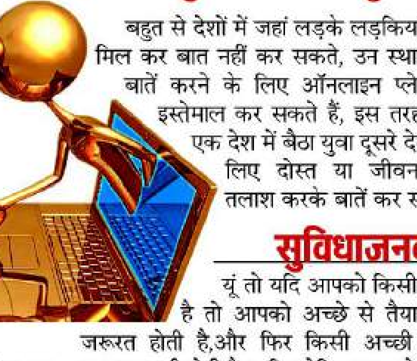

गुप्त नाम का फायदा

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा है नाम को गुप्त रखने की आजादी। आप किसी भी नाम और किसी भी फोटो के साथ अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हैं, कम्प्यूटर यह नहीं समझ पायेगा कि, आप झूठ बोल रहे हैं। आप किसी से या हर किसी से बात कर सकते हैं, और आपके वास्तविक जीवन की बुराई या कमियां जैसे, आपकी क्या हैसियत है ,और आप की योग्यता आदि कुछ भी हो, कोई फर्क नही पड़ता।

दुनियाभर में पहुंच

बहुत से देशों में जहां लड़के लड़कियां आपस में मिल कर बात नहीं कर सकते, उन स्थानों में लोग बातें करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से किसी एक देश में बैठा युवा दूसरे देश में अपने लिए दोस्त या जीवनसाथी की तलाश करके बातें कर सकता है।

सुविधाजनक

यूं तो यदि आपको किसी से मिलना है तो आपको अच्छे से तैयार होने की जरूरत होती है,और फिर किसी अच्छी जगह की तलाश करनी होती है आदि। लेकिन आपको ऑनलाइन चैटिंग के लिए सिर्फ एक इंटरनेट पैक और अच्छे ब्राउजर के अलावा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए लोग इन सब की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक- ऑनलाइन चैटिंग को वरीयता देते हैं।

बटन से कंट्रोल

हम ऑनलाइन कैसे दिखाई देते हैं इसका नियंत्रण हम सिर्फ एक बटन क्लिक कर के कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे के साथ स्मार्टफोन और लाखों फिल्टर से हम अपनी एक नकली इमेज आसानी से बना सकते हैं। कई बार तो लोगों को अपनी यह इमेज अपनी असली इमेज से ज्यादा पसंद आने लगती है, और इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन गपशप और बातचीत में चिपके रहते हैं। हम क्या कहते हैं, और किससे कहते हैं, इसका नियंत्रण भी खुद कर सकते हैं। इसके साथ यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग की इच्छा को भी बढ़ाता है।

साथियों का दबाव

जब ऑनलाइन प्लेटफार्म की शुरुआत हुई तो इसके फायदे तभी पता चले होंगे जब किसी ने पहली बार इसका उपयोग किया होगा। पहले तो हमें इसपर बात करने की आदत नहीं पड़ी थी। फिर इसका चलन बढ़ने के साथ साथियों का दबाव भी इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने के लिए महसूस किया जाने लगा, और ये भी एक बड़ा कारण था कि युवा एक दूसरे को ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते देख इसकी ओर आकर्षित होने लगे। अपनी उपलब्धियों और कहानियों को एक दूसरे से शेयर करने लगे। इस प्रकार एक यह ऐसा चक्र बन गया जो कभी कभी बहुत ज्यादा दोषपूर्ण बन जाता है। ऑनलाइन प्लेटफार्म के अधिक उपयोग से हम बिना किसी अनुशासन और नियंत्रण के चैटिंग करते है। जिससे हम असभ्य और अविवेकी बन सकते हैं। कई बार तो लोग किसी बहकावे में आकर उनका शिकार भी बन जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग करते समय हमें अधिक सतर्कता और संयम की आवश्यकता है।

मशहूर ब्रांड नेम्स की कहानी...

जहां तक ब्रांड की बात है ब्रांड और कुछ नहीं होता है सिर्फ कंपनी की अपनी एक पहचान होती है। कुछ ब्रांड ऐसे भी हैं जो की कई कंपनियों के उत्पादों की पहचान बन गए हैं। क्या कभी आपने सोचा है की किसी भी ब्रांड का नाम आखिर कैसे बनाया जाता है और आज के मशहूर ब्रांड्स के नाम किस प्रकार से बनें हैं। नाईक एक मशहूर ब्रांड है। इसका नाम एक ग्रीक देवी के नाम पर पड़ा है जो की विजय की देवी मानी जाती हैं और इस ब्रांड का चिन्ह उनकी उड़ान का प्रतीक है। बात कोको कोला की करें तो पता चलता है कि असल में इस पेय पदार्थ की मुख्य सामग्री कोला बेरिज और कोको की पत्तियां है इसलिए ही इसको कोको कोला नाम दिया गया है। ऐसे ही पेप्सी नाम एक पाचक एंजाइम पेप्सिन से लिया गया है, हालांकि यह पेप्सी में नहीं होता है। एडिडास ब्रांड का नाम इसके मालिक और निर्माता अडोल्फ डैस्सलर के नाम पर रख गया है असल में अडोल्फ का उपनाम एडि था। अमेजन ब्रांड के मालिक सीईओ जैफ बेजोस अपनी इस कंपनी का नाम ए शब्द से शुरू होने वाला ही रखना चाहते थे और वो चाहते थे की उनकी कंपनी में दुनिया का हर सामान बिके इसलिए उन्होंने इसका नाम चुनने के लिए उन्होंने सबसे बड़ी नदी का नाम चुना। सोनी ब्रांड का नाम लैटिन शब्द 'सोनस' से लिया गया है जिसका अर्थ होता है आवाज। वोडाफोन का मतलब आसान शब्दों में हैं वॉइस डाटा टेलीफोन है। नीविया ब्रांड नेम लैटिन शब्द 'निवेअस' से बना है जिसका अर्थ होता है बर्फ जैसा सफेद।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**